



ISSN: 2395-7852



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 5, September 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462

+91 9940572462

ijarasem@gmail.com

www.ijarasem.com

भारत में खालिस्तानी आंदोलन अतीत से वर्तमान तक

Dr.Dhiraj Bakolia

Professor, Dept. of Political Science, Govt.Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, पाकिस्तान राज्य पंजाब और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। 1984 में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार "खालिस्तान" नामक एक पुस्तिका में किया गया।

परिचय

खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान (पंजाबी : ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ , शाब्दिक अर्थ ' खालसा की भूमि ') नामक एक जातीय - धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है।^[2] खालिस्तान की प्रस्तावित सीमाएँ विभिन्न समूहों के बीच भिन्न-भिन्न हैं; कुछ लोग संपूर्ण सिख-बहुल भारतीय राज्य पंजाब का सुझाव देते हैं , जबकि बड़े दावों में पाकिस्तानी पंजाब और इसके अन्य हिस्से शामिल हैं उत्तर भारत जैसे चंडीगढ़ , हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।^[3] शिमला और लाहौर को खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है।^{[4][5]}

एक अलग सिख राज्य की मांग 1930 के दशक के दौरान शुरू हुई, जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने अंत के करीब था।^[6] 1940 में, खालिस्तान के लिए पहला स्पष्ट आह्वान "खालिस्तान" नामक एक पुस्तिका में किया गया था।^{[7][8]} प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन के साथ , यह आंदोलन भारत के पंजाब राज्य में - जहां सिख-बहुल आबादी है - फला-फूला - 1970 और 1980 के दशक तक जारी रहा और 1980 के दशक के अंत में अपने चरम पर पहुंच गया। सिख अलगाववादी नेता जगजीत सिंह चौहान ने दावा किया कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उनकी बातचीत के दौरान, भुट्टो ने खालिस्तान के लिए "संपूर्ण मदद" का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह समर्थन कभी सफल नहीं हुआ।^[9] 1990 के दशक में, उग्रवाद कम हो गया,^[10] और अलगाववादियों पर भारी पुलिस कार्रवाई, गुट्टीय अंदरूनी कलह और सिख आबादी से मोहभंग सहित कई कारणों से आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुंचने में विफल रहा।

ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए लोगों के विरोध में वार्षिक प्रदर्शनों के साथ, भारत और सिख प्रवासी समुदाय के भीतर कुछ समर्थन है।^{[11][12][13]} 2018 की शुरुआत में, भारत के पंजाब में पुलिस ने कुछ आतंकवादी समूहों को गिरफ्तार किया था।^[14] पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि हालिया उग्रवाद को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलेजेंस (आईएसआई) और कनाडा , इटली और यूके में "खालिस्तानी समर्थकों" का समर्थन प्राप्त है।^[15] सिमरनजीत सिंह मान 2022 में संगरूर से निर्वाचित, वर्तमान में भारतीय संसद में एकमात्र खुले तौर पर खालिस्तानी सांसद हैं और उनकी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) , वर्तमान में भारतीय संसद में एकमात्र खालिस्तान समर्थक पार्टी है।^{[16][17]}

1950 के दशक से पहले



सी. में महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य अपने चरम पर था। 1839 जिसका अधिकांश भाग वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है सिख दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में केंद्रित रहे हैं।^[18] अंग्रेजों द्वारा अपनी विजय से पहले, पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर सिख मिस्त्रों के संघ का शासन था। मिस्त्रों ने 1733 से 1799 तक पूर्वी पंजाब पर शासन किया,^[19] जब तक कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1799 से 1849 तक उनके संघ को सिख साम्राज्य में एकीकृत नहीं कर दिया गया।^[20]

1849 में द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के अंत में, सिख साम्राज्य को अलग-अलग रियासतों और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत में विघटित कर दिया गया।^[21] नए विजित क्षेत्रों में, "ब्रिटिश ' बांटो और राज करो ' प्रशासनिक नीतियों, हिंदू, सिखों और मुसलमानों को धर्मांतरित करने वाले ईसाई मिशनरियों की कथित सफलता और एक आम धारणा है कि पतन का समाधान के जवाब में धार्मिक-राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे भारत का धार्मिक समुदाय एक जमीनी स्तर का धार्मिक पुनरुत्थान था।"^[22]

1930 के दशक में जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ, सिखों ने सिख मातृभूमि के लिए अपना पहला आह्वान किया।^[6] जब मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग की गई, तो अकालियों ने इसे ऐतिहासिक रूप से सिख क्षेत्र को हड़पने के प्रयास के रूप में देखा।^{[23][24]} जवाब में, सिख पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एक ऐसे समुदाय के लिए तर्क दिया जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलग था।^[25] अकाली दल ने खालिस्तान की कल्पना एक धार्मिक राज्य के रूप में की थी जिसका नेतृत्व पटियाला के महाराजा के नेतृत्व में एक कैबिनेट की सहायता से किया गया था जिसमें अन्य इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल थे।^[26] देश में वर्तमान पंजाब, भारत, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान (लाहौर सहित) और शिमला हिल स्टेट्स के कुछ हिस्से शामिल होंगे।^[27]

भारत का विभाजन, 1947



1909 में ब्रिटिश पंजाब प्रांत

1947 में भारत के विभाजन से पहले, लुधियाना (जहाँ सिखों की आबादी 41.6% थी) के अलावा विभाजन-पूर्व ब्रिटिश पंजाब प्रांत के किसी भी जिले में सिख बहुमत में नहीं थे।^[28] बल्कि, प्रांत में इसके स्थान के आधार पर, क्षेत्र के जिलों में या तो हिंदू या मुसलमानों का बहुमत था।

ब्रिटिश भारत का विभाजन 1947 में धार्मिक आधार पर किया गया था, जहाँ पंजाब प्रांत को भारत और नव निर्मित पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। परिणामस्वरूप, अधिकांश सिख, हिंदुओं के साथ, पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत के पंजाब में चले गए,

जिसमें वर्तमान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। सिख आबादी, जो 1941 में कुछ पाकिस्तानी जिलों में 19.8% तक पहुंच गई थी, पाकिस्तान में घटकर 0.1% रह गई, और भारत को सौंपे गए जिलों में तेजी से बढ़ी। हालाँकि, वे अभी भी भारत के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक होंगे, जो हिंदू-बहुल प्रांत बना हुआ है।^[29]

पंजाब के साथ सिख संबंध (ओबेरॉय के माध्यम से)



वर्तमान भारतीय राज्य पंजाब का एक नक्शा। विभाजन के बाद, पूर्वी पंजाब PEPSU बन गया, जिसे 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ वर्तमान पंजाब राज्य के नए राज्यों के गठन के साथ विभाजित किया गया। पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ सिख बहुसंख्यक आबादी है।

सिख इतिहासकार हरजोत सिंह ओबेरॉय का तर्क है कि, सिखों और पंजाब के बीच ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद, क्षेत्र कभी भी सिख आत्म-परिभाषा का एक प्रमुख तत्व नहीं रहा है। उनका कहना है कि सिख धर्म के साथ पंजाब का जुड़ाव एक हालिया घटना है, जो 1940 के दशक से उपजी है।^[30] ऐतिहासिक रूप से, सिख धर्म अखिल भारतीय रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब (सिख धर्म का मुख्य धर्मग्रंथ) उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के संतों के कार्यों से लिया गया है, जबकि सिख धर्म की कई प्रमुख सीटें (उदाहरण के लिए पाकिस्तान में ननकाना साहिब, तख्त) बिहार में श्री पटना साहिब और महाराष्ट्र में हजूर साहिब) पंजाब के बाहर स्थित हैं।^[31]

ओबेरॉय का कहना है कि 1930 और 1940 के दशक के अंत में सिख नेताओं को एहसास हुआ कि पाकिस्तान में मुसलमानों और भारत में हिंदुओं का प्रभुत्व आसन्न था। पंजाब के भीतर एक अलग सिख राज्य को उचित ठहराने के लिए, सिख नेताओं ने यह तर्क देने के लिए मेटा-टिप्पणी और संकेत जुटाना शुरू कर दिया कि पंजाब सिखों का है और सिख पंजाब के हैं। इससे सिख समुदाय का क्षेत्रीयकरण शुरू हुआ।^[30]

सिख समुदाय के इस क्षेत्रीयकरण को मार्च 1946 में औपचारिक रूप दिया गया, जब अकाली दल की सिख राजनीतिक पार्टी ने पंजाब और सिख धार्मिक समुदाय के प्राकृतिक सहयोग की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।^[32] ओबेरॉय का तर्क है कि 20वीं सदी की शुरुआत में शुरुआत होने के बावजूद, एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में खालिस्तान 1970 और 1980 के दशक के अंत तक कभी भी एक बड़ा मुद्दा नहीं था जब इसका सैन्यीकरण शुरू हुआ।^[33]

1950 से 1970 के दशक तक

संप्रभु खालिस्तान के आह्वान की उत्पत्ति के बारे में दो अलग-अलग आख्यान हैं। एक भारत के भीतर की घटनाओं को संदर्भित करता है, जबकि दूसरा सिख प्रवासी की भूमिका को विशेषाधिकार देता है। ये दोनों आख्यान इस राज्य के लिए प्रस्तावित शासन के रूप (जैसे धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र) के साथ-साथ प्रस्तावित नाम (यानी सिखिस्तान बनाम खालिस्तान) में भिन्न हैं। यहां तक कि प्रस्तावित राज्य की सटीक भौगोलिक सीमाएं भी उनके बीच भिन्न हैं, हालांकि आमतौर पर इसे पंजाब के विभिन्न ऐतिहासिक निर्माणों में से एक से अलग करने की कल्पना की गई थी।^[34]

विचार-विमर्श

भारत में उद्भव

14 दिसंबर 1920 को स्थापित, अकाली दल एक सिख राजनीतिक दल था जो पंजाब में सरकार बनाने की मांग कर रहा था।^[35]

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, अकाली दल के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाबी लोगों के लिए एक प्रांत (सूबा) के निर्माण की मांग की। अकाली दल की मांगों में अधिकतम स्थिति एक संप्रभु राज्य (यानी खालिस्तान) की थी, जबकि इसकी न्यूनतम स्थिति भारत के भीतर एक स्वायत्त राज्य की थी।^[34] पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान उठाए गए मुद्दों को बाद में खालिस्तान के समर्थकों द्वारा एक अलग सिख देश के निर्माण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया।

चूंकि भारत के धार्मिक-आधारित विभाजन के कारण बहुत अधिक रक्तपात हुआ, इसलिए भारत सरकार ने शुरू में इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि पंजाबी-बहुल राज्य बनाने का मतलब प्रभावी रूप से एक बार फिर धार्मिक आधार पर राज्य बनाना होगा।^{[36][37]}

7 सितंबर 1966 को, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिसे 1 नवंबर 1966 से लागू किया गया। तदनुसार, पंजाब को पंजाब और हरियाणा राज्य में विभाजित किया गया, कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।^[38] जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब राज्य के निर्माण से सहमत थी लेकिन चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाने से इनकार कर दिया और इसे स्वायत्त बनाने से भी इनकार कर दिया। पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम इसके नेताओं की मांगों को पूरा करने में विफल रहा।^[39]

आनंदपुर संकल्प

चूंकि अब पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ साझा हो गई है, इसलिए पंजाब के सिखों में नाराजगी महसूस की गई।^[35] आगे की शिकायत को बढ़ाते हुए, रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर एक नहर प्रणाली स्थापित की गई, जो पंजाब से होकर बहती थी, ताकि पानी हरियाणा और राजस्थान तक भी पहुंच सके। परिणामस्वरूप, पंजाब को केवल 23% पानी मिलेगा जबकि शेष दो अन्य राज्यों को मिलेगा। तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा, इससे कांग्रेस के खिलाफ सिखों में नाराजगी बढ़ गई।^[35]

1972 के पंजाब चुनाव में अकाली दल की हार हुई।^[40] सार्वजनिक अपील हासिल करने के लिए, पार्टी ने 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सत्ता के आमूल-चूल हस्तांतरण और पंजाब को और स्वायत्तता देने की मांग की गई।^[41] संकल्प दस्तावेज़ में धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे शामिल थे, जिसमें सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के साथ-साथ चंडीगढ़ और कुछ अन्य क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इसने यह भी मांग की कि सत्ता को केंद्र से राज्य सरकारों को मौलिक रूप से हस्तांतरित किया जाए।^[42]

दस्तावेज़ को गोद लेने के बाद अगले दशक में ध्यान आकर्षित होने तक कुछ समय के लिए काफी हद तक भुला दिया गया था। 1982 में, अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाले ने प्रस्ताव को लागू करने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, यह महसूस करते हुए कि यह सिंचाई के लिए पानी के बड़े हिस्से और चंडीगढ़ की पंजाब को वापसी जैसी मांगों का वास्तविक समाधान है।^[43]

प्रवासी भारतीयों में उभार

'भारत के बाहर की घटनाओं' की कथा के अनुसार, विशेष रूप से 1971 के बाद, खालिस्तान की एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य की धारणा उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सिखों के बीच लोकप्रिय होने लगी। ऐसा एक विवरण खालिस्तान परिषद द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका पश्चिमी लंदन में ठिकाना था, जहां कहा जाता है कि खालिस्तान आंदोलन 1970 में शुरू किया गया था।^[34]

दर्विंदर सिंह परमार 1954 में लंदन चले गए। परमार के अनुसार, उनकी पहली खालिस्तान समर्थक बैठक में 20 से कम लोग शामिल हुए थे और केवल एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त करने पर उन्हें पागल करार दिया गया था। परमार ने अनुयायियों की कमी के बावजूद अपने प्रयास जारी रखे और अंततः 1970 के दशक में बर्मिंघम में खालिस्तानी झंडा फहराया।^[44] 1969 में, पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के दो साल बाद, भारतीय राजनेता जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए।^[45] चौहान के प्रस्ताव में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान के कुछ हिस्से भी शामिल थे।^[46]

परमार और चौहान 1970 में मिले और लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से खालिस्तान आंदोलन की घोषणा की, हालांकि समुदाय द्वारा इसे बिना किसी समर्थन के कट्टरपंथियों के रूप में खारिज कर दिया गया।^[44]

चौहान पाकिस्तान और अमेरिका में



पंजाब, पाकिस्तान में ननकाना साहिब का स्थान, जिसे जेडए भुट्टो द्वारा खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, चौहान ने चौधरी जहूर इलाही जैसे नेताओं के अतिथि के रूप में पाकिस्तान का दौरा किया। ननकाना साहिब और पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा करते हुए, चौहान ने एक स्वतंत्र सिख राज्य की धारणा को फैलाने के अवसर का उपयोग किया। पाकिस्तानी प्रेस द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित, उनकी टिप्पणियों के व्यापक कवरेज ने भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहली बार खालिस्तान की मांग से परिचित कराया। हालाँकि जनता के समर्थन की कमी के कारण, खालिस्तान शब्द अधिक से अधिक पहचाना जाने लगा।^[44] चौहान के अनुसार, प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान के भुट्टो ने ननकाना साहिब को खालिस्तान की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था।^[9]

13 अक्टूबर 1971 को, सिख प्रवासी समर्थकों के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करते हुए, चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्वतंत्र सिख राज्य की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन दिया। इस तरह के प्रचार से उन्हें प्रवासी भारतीयों से लाखों डॉलर इकट्ठा करने में मदद मिली,^[45] जिससे अंततः उनकी अलगाववादी गतिविधियों के संबंध में भारत में राजद्रोह और अन्य अपराधों से संबंधित आरोप लगाए गए।

खालिस्तान परिषद

1977 में भारत लौटने के बाद, चौहान ने 1979 में ब्रिटेन की यात्रा की। वहाँ, उन्होंने खालिस्तान परिषद की स्थापना की,^[47] 12 अप्रैल 1980 को आनंदपुर साहिब में इसके गठन की घोषणा की। चौहान ने खुद को परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया और बलबीर सिंह संधू ने इसके महासचिव के रूप में।

मई 1980 में, चौहान ने खालिस्तान के गठन की घोषणा करने के लिए लंदन की यात्रा की। इसी तरह की घोषणा संधू ने अमृतसर में की, जिन्होंने खालिस्तान के टिकट और मुद्रा जारी की। "खालिस्तान हाउस" नामक एक इमारत से संचालन करते हुए, चौहान ने एक कैबिनेट का नाम रखा और खुद को "खालिस्तान गणराज्य" का अध्यक्ष घोषित किया, प्रतीकात्मक खालिस्तान 'पासपोर्ट,' 'डाक टिकट,' और 'खालिस्तान डॉलर' जारी किए। इसके अलावा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में दूतावास चौहान द्वारा खोले गए।^[45] बताया गया है कि, एक धनी कैलिफ़ोर्नियाई पीच मैग्रेट के समर्थन से, चौहान ने अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक इकाडोरियन बैंक खाता खोला।^[46] कनाडा, अमेरिका और जर्मनी में विभिन्न समूहों के बीच संपर्क बनाए रखने के साथ-साथ, चौहान सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के संपर्क में रहे, जो एक धार्मिक सिख मातृभूमि के लिए अभियान चला रहे थे।^[45]

वैश्वीकृत सिख प्रवासी ने खालिस्तान के लिए प्रयासों और संसाधनों का निवेश किया, लेकिन जून 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार तक खालिस्तान आंदोलन वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य पर लगभग अदृश्य रहा।^[44]

ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्रभाव

भारत की विदेशी-खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व विशेष सचिव जीबीएस सिद्धू के बाद के खुलासे में, R&AW ने स्वयं ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए "खालिस्तान किंवदंती बनाने" में मदद की। सिख प्रवासियों के बीच "खालिस्तान समस्या" को देखने के लिए 1976 में ओटावा, कनाडा में तैनात होने के दौरान, सिद्धू को वहाँ तीन वर्षों के दौरान "कुछ भी गलत" नहीं मिला, [48] उन्होंने कहा कि "दिल्ली अनावश्यक रूप से एक तिल का पहाड़ बना रही थी जहाँ

कोई अस्तित्व में नहीं था," एजेंसी ने गैर-मौजूद खालिस्तान गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 1981 में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सात पद बनाए,^[48] उन्होंने सेना के ऑपरेशन तक अलगाववादी आंदोलन को "कल्पना" के रूप में वर्णित किया, जिसके बाद विद्रोह शुरू हो जाएगा।^[48]

ऑपरेशन के कुछ ही हफ्ते बाद लिखे गए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार, "स्वर्ण मंदिर पर छापे से पहले, न तो सरकार और न ही कोई अन्य व्यक्ति खालिस्तान आंदोलन पर ज्यादा भरोसा करता नजर आया। श्री भिंडरावाले ने खुद कई बार कहा था कि वह वह सिखों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग नहीं कर रहा था, केवल भारतीय संघ के भीतर पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था... सरकार द्वारा खालिस्तान प्रश्न उठाने के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि उसे अमृतसर में हत्या को उचित ठहराने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की जरूरत है। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल पर आक्रमण।"^[49]

सामुदायिक भावनाओं में भारी बदलाव का जिक्र करते हुए खुशवंत सिंह ने लिखा था कि "ऐसा लगता है कि मंदिर पर छापे के बाद से काफी खालिस्तान भावना पैदा हुई है, जिसे कई सिखों ने, यदि अधिकांश नहीं तो, अपने धर्म और अपनी संवेदनाओं पर गहरा आघात माना है।" सेना के हमले के बाद।^[49]

1970 के दशक के उत्तरार्ध से 1983 तक

दिल्ली एशियाई खेल (1982)

अकाली नेता, जिन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा की जीत की घोषणा करने की योजना बनाई थी, सहमत समझौते में बदलाव से नाराज थे। नवंबर 1982 में, अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने घोषणा की कि पार्टी जानबूझकर गिरफ्तार होने के लिए अकाली कार्यकर्ताओं के समूहों को दिल्ली भेजकर 9वें वार्षिक एशियाई खेलों को बाधित करेगी। पंजाब और हरियाणा के बीच क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर असहमति के कारण अकाली दल और सरकार के बीच अंतिम समय में बातचीत विफल हो गई।^[50]

यह जानते हुए कि खेलों को व्यापक कवरेज मिलेगा, अकाली नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच सिख "दुर्दशा" की धारणा को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली को प्रदर्शनकारियों की बाढ़ से भर देने की कसम खाई।^[50] खेलों से एक सप्ताह पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भजन लाल ने प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली-पंजाब सीमा को सील कर दिया,^[50] और पंजाब से दिल्ली आने वाले सभी सिख आगंतुकों की तलाशी लेने का आदेश दिया।^[51] हालाँकि ऐसे उपायों को सिखों द्वारा भेदभावपूर्ण और अपमानजनक माना गया, लेकिन वे प्रभावी साबित हुए क्योंकि अकाली दल केवल दिल्ली में छोटे और बिखरे हुए विरोध प्रदर्शन ही आयोजित कर सका। नतीजतन, कई सिख जो शुरू में अकालियों और भिंडरावाले का समर्थन नहीं करते थे, वे अकाली मोर्चा के प्रति सहानुभूति रखने लगे।^[50]

खेलों के समापन के बाद, लोंगोवाल ने दरबार साहिब में सिख दिग्गजों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें सेवानिवृत्त सहित बड़ी संख्या में सिख पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। मेजर जनरल शाबेग सिंह जो बाद में भिंडरावाले के सैन्य सलाहकार बने।^[50]

1984

बढ़ती उग्रवादी गतिविधि

1980 के दशक के पंजाब में भिंडरावाले के अनुयायियों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। इस काल के सशस्त्र खालिस्तानी उग्रवादी स्वयं को खार्कू बताते थे।^[52]

अकेले, वर्ष 1984 (1 जनवरी से 3 जून तक) में 775 हिंसक घटनाएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 298 लोग मारे गए और 525 घायल हुए।^[53]

हालाँकि यह सामान्य ज्ञान था कि ऐसे बम विस्फोटों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोग गुरुद्वारों में शरण ले रहे थे, भारत की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि वह सिख भावनाओं को आहत करने के डर से इन पूजा स्थलों में प्रवेश नहीं कर सकती।^[43] यहां तक कि हथियारों से भरे ट्रकों की खुली शिपिंग पर विस्तृत रिपोर्ट प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को भेजी गई थी, फिर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।^[43] अंततः, अक्टूबर 1983 में छह हिंदू बस यात्रियों की हत्या के बाद, पंजाब में आपातकालीन शासन लागू किया गया, जो एक दशक से अधिक समय तक जारी रहेगा।^[54]

संवैधानिक मुद्दे

फरवरी 1984 में अकाली दल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, खंड (2)(बी) के विरोध में और अधिक आंदोलन शुरू किया, जो अस्पष्ट रूप से बताता है कि "हिंदुओं के संदर्भ को सिख मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैन, या बौद्ध धर्म," सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देते हुए भी: "कृपाण धारण करना और साथ रखना सिख धर्म के पेशे

में शामिल माना जाएगा। " [55] :109 आज भी, संविधान के तहत ऐसे धर्मों को अलग से मान्यता देने में विफलता के कारण भारत में कई धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा इस खंड को अपमानजनक माना जाता है। [55]

अकाली दल के सदस्यों ने मांग की कि संविधान में सिखों को हिंदू के रूप में संदर्भित करने वाली किसी भी अस्पष्टता को हटाया जाए, क्योंकि यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सिख आबादी के लिए विभिन्न चिंताओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, एक सिख जोड़ा जो अपने धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करेगा, उसे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अपने मिलन को पंजीकृत कराना होगा। अकालियों ने ऐसे नियमों को सिख धर्म के लिए विशिष्ट कानूनों से बदलने की मांग की।

ऑपरेशन ब्लू स्टार

ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था, जिसका आदेश प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1 से 8 जून 1984 के बीच अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर (उर्फ स्वर्ण मंदिर) की इमारतों से उग्रवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए दिया था।, पंजाब - सिख धर्म में सबसे पवित्र स्थल। [56]

जुलाई 1983 में, अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंडरावाले को पवित्र मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया था, [57] जिस पर सरकार का आरोप था कि भिंडरावाले बाद में अपने सशस्त्र विद्रोह के लिए एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना लेगा। [58] [59]

धर्मयुद्ध मोर्चा की स्थापना से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की हिंसक घटनाओं में खालिस्तानी उग्रवादियों ने सीधे तौर पर 165 हिंदुओं और निरंकारियों के साथ-साथ भिंडरावाले का विरोध करने वाले 39 सिखों की हत्या कर दी थी, जबकि कुल मिलाकर 410 लोग मारे गए और 1,180 घायल हुए। खालिस्तानी हिंसा और दंगों का नतीजा। [60]

जैसे ही भिंडरावाले और उनके समर्थकों के साथ हुई बातचीत असफल साबित हुई, इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। [61] सेना के साथ, ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस शामिल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ (एक सिख) के नेतृत्व में सेना की इकाइयों ने 3 जून 1984 को मंदिर परिसर को घेर लिया। ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले, लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने सैनिकों को संबोधित किया: [62]

यह कार्रवाई सिखों या सिख धर्म के खिलाफ नहीं है; यह आतंकवाद के खिलाफ है। यदि उनमें से कोई है, जिसकी धार्मिक भावनाएँ प्रबल हैं या अन्य आपत्तियाँ हैं, और वह ऑपरेशन में भाग नहीं लेना चाहता है तो वह बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है, और यह उसके विरुद्ध नहीं माना जाएगा।

-लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़

हालाँकि, किसी भी सैनिक ने बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना, जिनमें कई "सिख अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक के अधिकारी" शामिल थे। [62] सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग करते हुए, सेना ने बार-बार उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने की मांग की, और उनसे लड़ाई शुरू करने से पहले कम से कम तीर्थयात्रियों को मंदिर परिसर छोड़ने की अनुमति देने को कहा।

शाम 7:00 बजे (IST) तक कुछ नहीं हुआ। [63] टैंक और भारी तोपखाने से सुसज्जित सेना ने उग्रवादियों की मारक क्षमता को बहुत कम आंका था, जिन्होंने भारी किलेबंदी वाले अकाल तख्त से एंटी-टैंक और मशीन-गन फायर से हमला किया था, और जिनके पास चीनी निर्मित रॉकेट थे- कवच-भेदी क्षमताओं के साथ चालित ग्रेनेड लांचर। 24 घंटे की गोलीबारी के बाद आखिरकार सेना ने मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया।

ऑपरेशन में भिंडरावाले मारा गया, जबकि उसके कई अनुयायी भागने में सफल रहे। सेना के हताहत आंकड़ों में 83 लोग मारे गए और 249 घायल हुए। [64] हालाँकि राजीव गांधी ने बाद में स्वीकार किया कि 700 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए। [65] भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक अनुमान के अनुसार, इस घटना के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 493 आतंकवादी और नागरिक हताहत हुए, साथ ही 1592 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। [66] स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार 5,000 से अधिक नागरिक और केवल 200 आतंकवादी हैं। [67]

ब्रिटेन के विदेश सचिव विलियम हेग ने ब्रिटेन की सेना द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों से हटकर, उग्रवादियों पर पूर्ण मोर्चे पर हमले के भारत सरकार के प्रयास को उच्च नागरिक हताहतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। [68] गांधी के विरोधियों ने भी अत्यधिक बल प्रयोग के लिए ऑपरेशन की आलोचना की। लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने बाद में कहा कि स्थिति के "पूरी तरह से खराब हो जाने" के कारण सरकार के पास "कोई अन्य सहारा नहीं" था: राज्य मशीनरी उग्रवादियों के नियंत्रण में थी; खालिस्तान की घोषणा आसन्न थी; और पाकिस्तान खालिस्तान के लिए अपने समर्थन की घोषणा करते हुए तस्वीर में आ जाता। [68]

बहरहाल, ऑपरेशन ने खालिस्तानी उग्रवाद को कुचल नहीं दिया, क्योंकि यह जारी रहा।^[33]

मित्रोखिन आर्काइव के अनुसार, 1982 में सोवियत ने नई दिल्ली रेजीडेंसी में "एजेंट एस" नामक एक भर्ती का इस्तेमाल किया, जो खालिस्तान के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में इंदिरा गांधी का करीबी था। एजेंट एस ने इंदिरा गांधी को धार्मिक गड़बड़ी पैदा करने और कथित तौर पर खालिस्तान साजिश शुरू करने के लिए पाकिस्तानी संलिप्तता दिखाने वाले झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराए। 1983 में राजीव गांधी की मास्को यात्रा के बाद, सोवियत ने उन्हें समझाया कि अमेरिका सिखों के लिए गुप्त समर्थन में लगा हुआ था। मित्रोखिन के अनुसार, 1984 तक, सोवियत द्वारा प्रदान की गई दुष्प्रचार ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित किया था।^{[69] [70] [71]}

इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे



इंदिरा गांधी

31 अक्टूबर 1984 की सुबह, ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी की उनके दो निजी सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों सिखों, ने हत्या कर दी थी।^[33] इस हत्या के कारण पूरे उत्तर भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। जबकि सत्तारूढ़ दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने कहा कि हिंसा स्वतःस्फूर्त दंगों के कारण हुई थी, इसके आलोचकों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सदस्यों ने स्वयं सिखों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाई थी।^[72]

दंगों की जांच के लिए बनाए गए एक विशेष आयोग नानावती आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस नेताओं (जगदीश टाइलर, एचकेएल भगत और सज्जन कुमार सहित) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दंगों की घटनाओं में भूमिका निभाई थी।^{[73] [74]} केंद्रीय मंत्री कमल नाथ पर रकाब गंज के पास दंगों का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।^[74] अन्य राजनीतिक दलों ने दंगों की कड़ी निंदा की।^[75] दो प्रमुख नागरिक-स्वतंत्रता संगठनों ने सिख विरोधी दंगों पर एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसमें बचे लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा आरोपी 16 महत्वपूर्ण राजनेताओं, 13 पुलिस अधिकारियों और 198 अन्य लोगों का नाम लिया गया।^[76]

परिणाम

1985 से आज तक

1985

कई सिख और हिंदू समूहों, साथ ही किसी भी धर्म से संबद्ध संगठनों ने खालिस्तान समर्थकों और भारत सरकार के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया है।^[1] विनाशकारी परिणामों के डर से अकालियों ने सिख राजनीति में कट्टरता देखी।^[35] जवाब में, राष्ट्रपति हरचंद सिंह लोंगोवाल ने अकाली दल के प्रमुख को बहाल कर दिया और एक शांति पहल पर जोर दिया, जिसने हिंदू-सिख मैत्री के महत्व को दोहराया, सिख चरमपंथी हिंसा की निंदा की, इसलिए घोषणा की कि अकाली दल खालिस्तान के पक्ष में नहीं है।

1985 में, भारत सरकार ने राजीव-लोंगोवाल समझौते के माध्यम से सिखों की शिकायतों का राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास किया, जो लोंगोवाल और प्रधान मंत्री राजीव गांधी के बीच हुआ था। समझौता - सिखों की धार्मिक, क्षेत्रीय और आर्थिक मांगों को मान्यता देते हुए, जिनके बारे में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में समझौता नहीं किया जा सकता था - चंडीगढ़ मुद्दे और नदी विवाद को

हल करने के लिए आयोग और स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिसका आधार तैयार किया गया आने वाले चुनाव में अकाली दल की जीत के लिए।^[35]

सामान्य स्थिति में वापसी के लिए आधार प्रदान करते हुए, चंडीगढ़ स्पष्ट रूप से एक मुद्दा बना रहा और समझौते की सिख उग्रवादियों ने निंदा की, जिन्होंने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग छोड़ने से इनकार कर दिया। इन चरमपंथियों ने, जो अप्रसन्न रह गए थे, लोंगोवाल की हत्या करके प्रतिक्रिया व्यक्त की।^[59] इस तरह के व्यवहार से वार्ता को खारिज कर दिया गया, जिससे कांग्रेस और अकाली दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया।^[35]

भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आंदोलन को बढ़ावा देने का जिम्मा करते हुए "विदेशी हाथ" की संलिप्तता की ओर इशारा किया। पंजाब ने भारत सरकार को बताया कि आतंकवादी देश के बाहर के स्रोतों के माध्यम से और देश के भीतर के स्रोतों के साथ संबंध विकसित करके परिष्कृत हथियार प्राप्त करने में सक्षम थे।^[35] इस प्रकार, सरकार का मानना था कि हथियारों का बड़ा अवैध प्रवाह भारत की सीमाओं से होकर बह रहा था, हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को शरण, हथियार, धन और नैतिक समर्थन प्रदान किया, हालांकि अधिकांश आरोप परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थे।^[35]

एयर इंडिया फ्लाइट 182



आयरिश नौसेना सेवा एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी के बाद शवों को बरामद कर रही है



इसमें शामिल विमान, वीटी-ईएफओ, एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी से दो सप्ताह से भी कम समय पहले 10 जून 1985 को देखा गया था।

एयर इंडिया फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल - लंदन - दिल्ली - बॉम्बे मार्ग पर चलने वाली एयर इंडिया की उड़ान थी। 23 जून 1985 को, मार्ग पर चलने वाले एक बोइंग 747 को आयरलैंड के तट के पास हवा में एक बम द्वारा उड़ा दिया गया था। विमान में सवार कुल 329 लोग मारे गए,^[77] 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और 24 भारतीय नागरिक, जिनमें विमान चालक दल भी शामिल था। उसी दिन, एक सामान बम के कारण हुआ विस्फोट आतंकवादी ऑपरेशन से जुड़ा था और नारिता हवाई अड्डे पर हुआ था। जापान के टोक्यो में, एयर इंडिया की उड़ान 301 के उद्देश्य से, दो सामान संभालने वालों की मौत हो गई। पूरी घटना का दायरा अंतर-महाद्वीपीय था, जिसमें कुल मिलाकर 331 लोग मारे गए और विभिन्न महाद्वीपों के पांच देश प्रभावित हुए: कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, भारत, जापान और आयरलैंड।

बमबारी में मुख्य संदिग्ध बब्बर खालसा नामक एक सिख अलगाववादी समूह और अन्य संबंधित समूहों के सदस्य थे, जो उस समय भारत के पंजाब में एक अलग सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे थे। सितंबर 2007 में, कनाडाई जांच आयोग ने उन रिपोर्टों की जांच की, जिनमें शुरुआत में भारतीय खोजी समाचार पत्रिका तहलका में खुलासा किया गया था,^[78] कि अब तक अज्ञात व्यक्ति, लखबीर सिंह रोडे ने विस्फोटों का मास्टरमाइंड किया था। हालांकि, निष्कर्ष में दो अलग-अलग कनाडाई पूछताछ ने आधिकारिक तौर पर निर्धारित किया कि आतंकवादी ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड वास्तव में कनाडाई, तलविंदर सिंह परमार था।^[79]

एयर इंडिया पर बमबारी के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कनाडाई नागरिक और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सदस्य इंद्रजीत सिंह रेयात, जिन्होंने 2003 में मानव वध के लिए दोषी ठहराया था, इस मामले में दोषी ठहराए गए एकमात्र व्यक्ति होंगे।^{[80][81]} एयर इंडिया फ्लाइट 182 और नारिता हवाई अड्डे पर विस्फोट हुए बमों को असेंबल करने के लिए उन्हें पंद्रह साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।^[82]

1980 के दशक के अंत में

1986 में, जब उग्रवाद अपने चरम पर था, स्वर्ण मंदिर पर फिर से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और दमदमी टकसाल के उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। उग्रवादियों ने एक सभा (सरबत खालसा) बुलाई और 26 जनवरी को खालिस्तान के निर्माण के पक्ष में एक प्रस्ताव (गुरमत्ता) पारित किया।^[83] हालाँकि, केवल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के पास सिखों की सर्वोच्च धार्मिक-अस्थायी सीट, जत्थेदार की नियुक्ति का अधिकार था। इस प्रकार उग्रवादियों ने एसजीपीसी को भंग कर दिया और अपना स्वयं का जत्थेदार नियुक्त कर दिया, जिसने उनकी बोली को भी अस्वीकार कर दिया। उग्रवादी नेता गुरबचन सिंह मनोचाहलइस प्रकार उसने स्वयं को बलपूर्वक नियुक्त किया।^[84]

29 अप्रैल 1986 को, अकाल तख्त पर अलगाववादी सिखों की एक सभा ने खालिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की,^[85] और खालिस्तान के पक्ष में कई विद्रोही आतंकवादी समूहों ने बाद में भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह छेड़ दिया। क्षेत्र में सामान्य स्थिति लौटने से पहले पंजाब में एक दशक तक हिंसा और संघर्ष चलेगा। विद्रोह के इस दौर में सिख उग्रवादियों की पुलिस के साथ-साथ निरंकारियों, एक रहस्यमय सिख संप्रदाय, जो सिख धर्म में सुधार के अपने उद्देश्यों में कम रूढ़िवादी हैं, के साथ झड़पें देखी गईं।^[86]

खालिस्तानी उग्रवादी गतिविधियाँ कई हमलों के रूप में प्रकट हुईं, जैसे 1987 में लालरू के पास 32 हिंदू बस यात्रियों का नरसंहार, और 1991 में लुधियाना में 80 ट्रेन यात्रियों की हत्या।^[87] इस तरह की गतिविधियाँ 1990 के दशक में भी जारी रहीं क्योंकि 1984 के दंगों के अपराधियों को सजा नहीं मिली, जबकि कई सिखों को भी लगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके धार्मिक अधिकारों को दबाया जा रहा है।^[88]

1989 के संसदीय चुनावों में, सिख अलगाववादी प्रतिनिधि पंजाब की 13 राष्ट्रीय सीटों में से 10 पर विजयी रहे और उन्हें सबसे अधिक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ।^[89] कांग्रेस ने उन चुनावों को रद्द कर दिया और इसके बजाय खाकी चुनाव की मेजबानी की। अलगाववादियों ने मतदान का बहिष्कार किया। मतदान प्रतिशत 24% था। कांग्रेस ने यह चुनाव जीता और इसका इस्तेमाल अपने अलगाववाद विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किया। 1993 के अंत तक अधिकांश अलगाववादी नेतृत्व का सफाया हो गया और नरमपंथियों का दमन कर दिया गया।^[90]

1990 के दशक

भारतीय सुरक्षा बलों ने 1990 के दशक की शुरुआत में विद्रोह को दबा दिया, जबकि खालसा राज पार्टी और एसएडी (ए) जैसे सिख राजनीतिक समूहों ने अहिंसक तरीकों से एक स्वतंत्र खालिस्तान का प्रयास जारी रखा।^{[91][92][93]} वहीं जिला तरनतारन के गांव भिखीविंड में आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए 'संधू' परिवार ने आखिरी दिन की तरह हर रोज लड़ाई लड़ी और कई बार आतंकवादियों को हराया। ऐसी ही एक घटना 30 सितंबर 1990 की है, जब करीब 200 आतंकवादियों ने बलविंदर सिंह के घर पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में, संधू परिवार ने राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का उपयोग करके कई आतंकवादियों को मार डाला और बाकी आतंकवादियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। परिवार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया अत्यंत विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस दिखाने के लिए।^[94]

अगस्त 1991 में, रोमानिया में तत्कालीन भारतीय राजदूत जूलियो रिबेरो पर बुखारेस्ट में पंजाबी सिखों के रूप में पहचाने गए बंदूकधारियों द्वारा हत्या के प्रयास में हमला किया गया और घायल कर दिया गया।^{[95][88]} सिख समूहों ने 1991 में नई दिल्ली में रोमानियाई प्रभारी लिविउ राडू के अपहरण की जिम्मेदारी भी ली। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिबेरो की हत्या के प्रयास के संदेह में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्यों की रोमानियाई गिरफ्तारी के प्रतिशोध में था।^{[88][96]} सिख राजनेताओं द्वारा कार्रवाई की आलोचना के बाद राडू को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया।^[97]

अक्टूबर 1991 में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि अपहरण से पहले के महीनों में हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई थी, भारतीय सुरक्षा बलों या सिख आतंकवादियों ने प्रतिदिन 20 या अधिक लोगों की हत्या कर दी थी, और आतंकवादी परिवार के सदस्यों को "गोलियां मार" रहे थे। पुलिस अधिकारियों का।^[88] विद्वान इयान टैलबोट का कहना है कि भारतीय सेना, पुलिस और उग्रवादियों सहित सभी पक्षों ने हत्या, बलात्कार और यातना जैसे अपराध किए।^[98]

24 जनवरी 1993 से 4 अगस्त 1993 तक खालिस्तान एनजीओ अनरिप्रेजेंटेटिव नेशंस एंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन का सदस्य था। 22 जनवरी 1995 को सदस्यता स्थायी रूप से निलंबित कर दी गई।^[99]

31 अगस्त 1995 को एक आत्मघाती बम विस्फोट में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की मौत हो गई, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक समूह बब्बर खालसा ने ली। हालाँकि, सुरक्षा अधिकारियों ने समूह की भागीदारी को संदिग्ध बताया है।^[100] नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास द्वारा 2006 की एक प्रेस विज्ञप्ति में संकेत दिया गया कि जिम्मेदार संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स था।^[101]

जबकि पहले के दौर में उग्रवादियों को सिख अलगाववादियों का कुछ समर्थन प्राप्त था, लेकिन यह समर्थन धीरे-धीरे खत्म हो गया।^[102] उग्रवाद ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और राज्य में हिंसा में वृद्धि हुई। घटते समर्थन और तेजी से प्रभावी भारतीय सुरक्षा सैनिकों द्वारा राज्य-विरोधी लड़ाकों को खत्म करने के साथ, 1990 के दशक की शुरुआत में सिख आतंकवाद प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।^[103]

-2000

प्रतिकार

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों (सिख पुलिस अधिकारी, केपीएस गिल के नेतृत्व में) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि फर्जी गोलीबारी में हजारों संदिग्ध मारे गए और हजारों शवों का उचित पहचान या पोस्ट के बिना अंतिम संस्कार/निपटान कर दिया गया। मरणोपरांत।^{[104][105][106][107]} ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि, 1984 के बाद से, सरकारी बलों ने उग्रवादियों से लड़ने के लिए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों का सहारा लिया है, जिनमें शामिल हैं: मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखना, यातना देना, और सारांश निष्पादन। नागरिकों और संदिग्ध उग्रवादियों की पुलिस द्वारा मांगे गए रिश्तेदारों के बारे में बताने के लिए परिवार के सदस्यों को बार-बार हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया।^{[108][109]} एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पंजाब विद्रोह के दौरान पुलिस द्वारा गायब होने, यातना, बलात्कार और गैरकानूनी हिरासत के कई मामलों का आरोप लगाया है, जिसके लिए दिसंबर 2002 तक 75-100 पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था।^[110]

2010 के दशक

खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 2010 के दशक में की गई गतिविधियों में तरनतारन विस्फोट शामिल है, जिसमें पुलिस कार्रवाई में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक ने खुलासा किया कि उन्हें भारत में कई डेरा नेताओं को मारने के लिए सिख फॉर जस्टिस द्वारा आदेश दिया गया था।^{[111][112]} दल खालसा जैसे खालिस्तान समर्थक संगठन भारत के बाहर भी सक्रिय हैं, जिन्हें सिख प्रवासी के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त है।^[113] 25 दिसंबर तक, भारतीय मीडिया सूत्रों के अनुसार, बब्बर खालसा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा पंजाब में संभावित हमले के बारे में कई एजेंसियों द्वारा इनपुट दिए गए हैं, कथित तौर पर वे अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में हैं और हथियारों की तस्करी की कोशिश कर रहे हैं। सीमा पार।^{[114][115]}

नवंबर 2015 में, पंजाब क्षेत्र में हालिया अशांति के जवाब में सिख समुदाय (यानी सरबत खालसा) की एक मंडली बुलाई गई थी। सरबत खालसा ने सिख संस्थानों और परंपराओं को मजबूत करने के लिए 13 प्रस्ताव अपनाए। 12वें प्रस्ताव में 1986 में सरबत खालसा द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों की पुष्टि की गई, जिसमें खालिस्तान के संप्रभु राज्य की घोषणा भी शामिल थी।^[116]

इसके अलावा, खालिस्तान के पक्ष में संकेत तब उठाए गए जब शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने सूरत सिंह खालसा से मुलाकात की, जो दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) में भर्ती थे। जब मान एसीपी सतीश मल्होत्रा से बहस कर रहे थे, तभी डीएमसीएच के मुख्य द्वार पर खड़े समर्थकों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खालिस्तान के निशान लहराये। लगभग 15-20 मिनट तक चले पुलिस अधिकारियों के साथ टकराव के बाद, मान को एडीसीपी परमजीत सिंह पन्नू के साथ खालसा से मिलने की अनुमति दी गई।^[117]

अपनी संस्कृति और धर्म के साथ निरंतर संबंध बनाए रखते हुए, भारत के बाहर सिख प्रवासी अपने निवास वाले देशों में वित्तीय सहायता, प्रचार और राजनीतिक पैरवी के माध्यम से आंदोलन का तेजी से समर्थन कर रहे हैं और आंदोलन को चलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। व्यापक राजनीतिक और वित्तीय संबंधों से उत्साहित होकर, प्रवासी भारतीयों ने पंजाब में आंदोलन के लिए वित्तीय और राजनयिक सहायता फैलाने के लिए अन्य उपलब्ध प्रतिष्ठानों के अलावा गुरुद्वारों का उपयोग किया है और इसके लिए समर्थन जुटाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग किया है।^[118]

हाल ही में कई जगहों पर खालिस्तान आंदोलन के समर्थन में कई संकेत सामने आए हैं, हालांकि कनाडा के आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड (आईआरबी) की रिपोर्ट है कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों को खुद हिरासत में लिया जा सकता है और प्रताड़ित किया जा सकता है।^[119] विशेष रूप से, ऑपरेशन ब्लूस्टार की 31वीं वर्षगांठ पर, पंजाब में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 25 सिख युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।^[120] पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के एक कार्यक्रम के दौरान भी खालिस्तान समर्थक नारे लगाये गये। शिअद-ए के दो सदस्यों, जिनकी पहचान सरूप सिंह संधा और राजिंदर सिंह चन्ना के रूप में की गई है, ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान खालिस्तान समर्थक और बादल विरोधी संकेत उठाए।^[121]

पीछे मुड़कर देखें तो खालिस्तान आंदोलन कई कारणों से भारत में अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में विफल रहा है:

- पंजाब पुलिस प्रमुख केपीएस गिल के नेतृत्व में अलगाववादियों पर भारी पुलिस कार्रवाई।^[14] कई उग्रवादी नेता मारे गए और अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया और पुनर्वास किया।^[84]
- गिल आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रावधान को जोड़कर नीतियों में बदलाव को गिरावट का श्रेय देते हैं। बिना किसी हस्तक्षेप के सरकार की ओर से स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति।^[84]

- चरमपंथी समर्थकों के लिए भी 'खालिस्तान' की स्पष्ट राजनीतिक अवधारणा का अभाव. कुमार (1997) के अनुसार, जो नाम इच्छाधारी सोच वाला था वह केवल भारतीय प्रतिष्ठान के प्रति उनके घृणा का प्रतिनिधित्व करता था और उन्हें इसका कोई विकल्प नहीं मिला।^[122]
- आंदोलन के बाद के चरणों में उग्रवादियों के पास वैचारिक प्रेरणा का अभाव था।^[84]
- इसके रैंकों में अपराधियों और सरकार के वफादारों के प्रवेश ने समूहों को और विभाजित कर दिया।^[84]
- पंजाब की सिख आबादी से सहानुभूति और समर्थन की हानि।^[84]
- सिक्खों के बीच फूट ने भी इस आंदोलन को कमजोर कर दिया। पेटीग्रेव के अनुसार गैर- जाट शहरी सिख "जाटिस्तान" देश में नहीं रहना चाहते थे।^{[123][124]} आगे विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से पुलिस और सैन्य सेवा को करियर विकल्प के रूप में पसंद करते थे। पंजाब पुलिस में बहुसंख्यक जाट सिख थे और पुलिस प्रमुख गिल ने इस संघर्ष को "जाट बनाम जाट" कहा था।^[84]
- प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल के उदारवादी गुटों ने तीनों विधानसभा (अर्थात् संसदीय) और एसजीपीसी चुनावों के माध्यम से राज्य में राजनीतिक पदों पर पुनः कब्जा कर लिया। उग्रवादी-संबद्ध गुटों पर पारंपरिक राजनीतिक दलों का प्रभुत्व फिर से कायम हो गया।^[125]
- अलगाववादी तत्वों के उदय के खिलाफ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ गई है।^[126]
- सिख समुदाय द्वारा अपनाए गए विश्वास बहाली के उपायों ने खालिस्तान आंदोलन को जड़ से उखाड़ने में मदद की।^[126]

इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के लिए लिखते हुए सिमरत ढिल्लों (2007) ने कहा कि हालांकि कुछ समूहों ने लड़ाई जारी रखी, "आंदोलन ने भारत और प्रवासी समुदाय दोनों में अपना लोकप्रिय समर्थन खो दिया है।"^[127]

2020

अगस्त 2022 में, एक स्वघोषित, कट्टरपंथी^[131] उपदेशक अमृतपाल सिंह, दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब डी के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के बाद प्रमुखता में आए (सिद्धू के रिश्तेदारों और कुछ सहयोगियों द्वारा उत्तराधिकार को नाजायज बताया गया)।^{[132][133][134][135]} बाद में उन्होंने खालिस्तान के निर्माण और सिक्खों को बपतिस्मा लेने, धार्मिक तपस्या अपनाने और नशीली दवाओं और अन्य बुराइयों से दूर रहने की वकालत करते हुए एक अभियान और कई उपदेश यात्राएं शुरू कीं।^{[136][137]} उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान हिंसा और हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन किया।^[138] मार्च 2022 में, भारतीय अधिकारियों ने वारिस पंजाब डे पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें संगठन पर हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और पंजाब में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया।^[139] 35 दिनों तक फरार रहने के बाद अंततः उसे 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया।^[140]

सिंह की गिरफ्तारी के बाद, विशेषकर प्रवासी सिक्खों के बीच, कई विरोध प्रदर्शन हुए। जबकि कई घटनाएँ बिना किसी घटना के घटित हुईं, विभिन्न स्थानों पर कई हिंसक हमलों की सूचना मिली। प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, एक अन्य भीड़ ने लंदन में भारतीय उच्चायोग कार्यालय पर हमला किया और पोल से भारतीय ध्वज को उतारने का प्रयास किया, खिड़कियाँ तोड़ दीं और सुरक्षा कर्मचारियों को मामूली चोटें पहुंचाईं।^{[141][142][143]} एनआईए ने दावा किया है कि सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शनकारियों के एक समूह को भारत सरकार के सभी प्रतिनिधियों को मारने के लिए उकसाया गया था।^[144] इसके अलावा, दो लोगों ने वाणिज्य दूतावास के प्रवेश द्वार पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और इमारत में आग लगाने का प्रयास किया।^[145] वाशिंगटन में, खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे एक भारतीय पत्रकार को मौखिक रूप से धमकाया और शारीरिक हमला किया।^[146] सरे में, एक अन्य पत्रकार पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया और उसे परेशान किया गया।^[147] अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू को खालिस्तानियों द्वारा हत्या की धमकी दी गई थी।^[148]

18 जून 2022 को, ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख मंदिर की पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर कथित तौर पर कनाडा में दो खालिस्तान समर्थक संगठनों का प्रमुख था, और भारत सरकार ने उस पर भारत में लक्षित हत्याएं कराने का आरोप लगाया था, जिसके लिए उसने उसके प्रत्यर्पण की असफल मांग की थी।^[149]

2 जुलाई को खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी।^[150] सैन फ्रांसिस्को विभाग द्वारा आगजनी के प्रयास को तुरंत दबा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इमारत को सीमित क्षति हुई और उपस्थित कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई।^[151] विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस घटना की निंदा की।^[152] खालिस्तानी समर्थकों द्वारा ट्विटर पर घटना का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि यह हमला हरदीप सिंह निज्जर की हाल ही में हुई मौत का प्रतिशोध था।^[151] निज्जर की मौत ने सिख प्रवासी वर्गों के बीच रैलियां निकालीं, इन घटनाओं को बढ़ावा देने वाले पोस्टरों में आरोप लगाया गया कि भारतीय राजनयिकों ने मौत में भूमिका निभाई। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने पोस्टरों की निंदा की, जिन्होंने भारतीय राजनयिकों और इमारतों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।^[153] हालांकि, 18 सितंबर को, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई खुफिया उनकी हत्या को भारत सरकार के साथ जोड़कर "विश्वसनीय आरोप" लगा रही थी, उन्होंने भारत से हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग करने का आह्वान किया।^{[154][155]} न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने कहा कि "न्याय की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी" और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।^[156] कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा ने एक शीर्ष

रैकिंग वाले भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार, जवाब में, भारत ने "शीर्ष कनाडाई जासूस" को निष्कासित कर दिया।^[157] भारत सरकार ने एक बयान जारी कर सभी आरोपों को "बेतुका और प्रेरित" बताया।^[157]

आतंकवाद

1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में, पंजाब में कट्टरपंथी राज्य उग्रवाद में नाटकीय वृद्धि हुई थी। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य ऑपरेशन ब्लू स्टार ने कई सिखों को आहत किया।^[158] अलगाववादियों ने इस घटना का, साथ ही 1984 के बाद के सिख विरोधी दंगों का उपयोग यह दावा करने के लिए किया कि भारत में सिखों के हित सुरक्षित नहीं हैं और पंजाब में सिखों के बीच उग्रवाद के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। सिख प्रवासी के कुछ वर्ग भी वित्तीय और राजनयिक समर्थन के साथ अलगाववादियों में शामिल होने लगे।^[33]

पंजाब में सिखों का एक वर्ग उग्रवाद की ओर मुड़ गया और 1980 और 1990 के दशक में कई सिख आतंकवादी संगठन फैल गए।^[30] कुछ उग्रवादी समूहों का लक्ष्य भारतीय सरकार, सेना या बलों के सदस्यों पर हिंसा के कृत्यों के माध्यम से एक स्वतंत्र राज्य बनाना था। बड़ी संख्या में सिखों ने उग्रवादियों की कार्रवाई की निंदा की।^[159] मानवशास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार, युवाओं के उग्रवादी और अन्य धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों में शामिल होने का एक कारण मौज-मस्ती, उत्साह और पुरुषत्व की अभिव्यक्ति थी। पुरी, जज और सेखों (1999) का सुझाव है कि अशिक्षित/अल्पशिक्षित युवा, जिनके पास नौकरी की पर्याप्त संभावनाएं नहीं थीं, वे "मौज-मस्ती" के प्राथमिक उद्देश्य के लिए खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों में शामिल हो गए थे।^[160] उन्होंने उल्लेख किया है कि खालिस्तान की खोज केवल 5% "आतंकवादियों" के लिए प्रेरणा थी।^{[125] [160]}

उग्रवादी समूह

खालिस्तान काउंसिल जैसे कई उग्रवादी सिख समूह हैं, जो वर्तमान में सक्रिय हैं और सिख समुदाय को संगठन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दुनिया भर में कई समूह संगठित हैं, जो खालिस्तान के लिए अपने सैन्य प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। ऐसे समूह 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में सबसे अधिक सक्रिय थे, और तब से उनकी गतिविधि कम हो गई है। ये समूह भारत में काफी हद तक खत्म हो चुके हैं लेकिन सिख प्रवासियों के बीच उनकी अभी भी राजनीतिक उपस्थिति है, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों में जहां उन्हें कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।^[161]

इनमें से अधिकांश संगठनों को 1993 में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान कुचल दिया गया था। हाल के वर्षों में सक्रिय समूहों में बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, दल खालसा और भिंडरावाले टाइगर फोर्स शामिल हैं। इससे पहले एक अज्ञात समूह, शहीद खालसा फोर्स ने 1997 में नई दिल्ली में बाज़ार में हुए बम विस्फोटों का श्रेय लेने का दावा किया था। तब से इस समूह के बारे में कभी नहीं सुना गया है।

प्रमुख खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों में शामिल हैं:

- बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई)
 - यूरोपीय संघ,^[162] कनाडा,^[163] भारत,^[164] और यूके में एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध।^{[164] [165]}
 - 2004 में अमेरिकी सरकार की आतंकवादी बहिष्करण सूची में शामिल किया गया।^[166]
 - 27 जून 2002 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बमबारी के लिए अमेरिका और कनाडाई अदालतों द्वारा नामित।^{[164] [167]}
- भिंडरावाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान (बीटीएफके; उर्फ भिंडरावाले टाइगर फोर्स, बीटीएफ)
 - ऐसा प्रतीत होता है कि इस समूह का गठन 1984 में गुरबचन सिंह मनोचाहल द्वारा किया गया था।
 - ऐसा प्रतीत होता है कि मनोचाहल की मृत्यु के बाद यह विघटित हो गया है या अन्य संगठनों में एकीकृत हो गया है।^[168]
 - 1995 में खालिस्तान आंदोलन में 4 "प्रमुख आतंकवादी समूहों" में से एक के रूप में सूचीबद्ध।^[169]
- खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ)^[30]
 - 1986 में सरबत खालसा द्वारा गठित।^[170] यह अमेरिकी विदेश विभाग (डीओएस) द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं है।^[171]
 - डीओएस^[101] और पंजाब पुलिस इंटे्लिजेंस डिवीजन के सहायक महानिरीक्षक,^[172] के अनुसार केसीएफ भारत में हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 1995 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या भी शामिल थी।^[101]
- खालिस्तान लिबरेशन आर्मी (KLA)
 - खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की एक शाखा, उससे संबद्ध या उससे अलग हुए समूह के रूप में प्रतिष्ठित।
- खालिस्तान लिबरेशन फोर्स^[30]
 - 1986 में गठित

- 1980 और 1990 के दशक के दौरान भारत में नागरिक ठिकानों पर कई बमबारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ^{[173][174]} कभी-कभी इस्लामी कश्मीर अलगाववादियों के साथ मिलकर। ^[175]
- खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF)
 - यूरोपीय संघ द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध। ^[162]
 - आखिरी बड़ी संदिग्ध गतिविधि 2006 में जालंधर में अंतर-राज्य बस टर्मिनल पर एक बम विस्फोट था। ^[176]
- इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ), ^[30] यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISSF)
- दशमेश रेजिमेंट
- शहीद खालसा फोर्स

निष्कर्ष

उपशमन

अमेरिकी विदेश विभाग ने पाया कि 1992 से 1997 तक सिख चरमपंथ में काफी कमी आई है, हालांकि 1997 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि "सिख आतंकवादी कोशिकाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं और चरमपंथी विदेशी सिख समुदायों से धन इकट्ठा करते हैं।" ^[177]

1999 में, Rediff.com के लिए लिखते हुए, कुलदीप नैयर ने "यह फिर से कट्टरवाद है" शीर्षक से एक लेख में कहा कि सिख "जनता" ने आतंकवादियों को खारिज कर दिया है। ^[178] 2001 तक, सिख उग्रवाद और खालिस्तान की मांग लगभग समाप्त हो गई थी। ^[iii]

ऑफ़लिया सेंटर फॉर ग्लोबल एंड इंटरनेशनल स्टडीज, यूसीएसबी के निदेशक मार्क जुएर्गसमेयर ने "भिंडरावाले से बिन लादेन तक: धार्मिक हिंसा को समझना" शीर्षक वाले अपने पेपर में एक उग्रवादी का साक्षात्कार लिया, जिसने कहा कि "आंदोलन खत्म हो गया है," जैसा कि उनके कई सहकर्मी मारे गए, कैद किए गए, या छिपने के लिए प्रेरित किए गए, और क्योंकि जनता का समर्थन खत्म हो गया था। ^[179]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. शाह, मुर्तजा अली (27 जनवरी 2022)। "वाशिंगटन में गांधी प्रतिमा पर खालिस्तान का झंडा लगाया गया"। जियो न्यूज। 31 जुलाई 2022 को मूल से संग्रहीत। 31 जुलाई 2022 को लिया गया।
2. ^ किन्नवाल, कैटरीना (24 जनवरी 2007)। "भारत में सिख और हिंदू राष्ट्रवाद की स्थिति"। भारत में वैश्वीकरण और धार्मिक राष्ट्रवाद: ओण्टोलॉजिकल सुरक्षा की खोज। रूटलेज। आईएसबीएन 978-1-13-413570-7. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 14 अगस्त 2015 को लिया गया।
3. ^ क्रेशॉ, मार्था, 1995, संदर्भ में आतंकवाद, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, आईएसबीएन 978-0-271-01015-1 पी। 364
4. ^ कैटन, नाओमी (10 जून 2022)। "प्रतिबंधित एसएफजे नेता ने लाहौर में पाक प्रेस के सामने 'खालिस्तान मानचित्र' का अनावरण किया, जिसमें शिमला को 'राजधानी' बताया गया"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 10 फरवरी 2022 को मूल से संग्रहीत। 26 मार्च 2022 को लिया गया।
5. ^ महताब अली शाह, पाकिस्तान की विदेश नीति 1997, पीपी 24-25।
6. ^ एबी एक्सल, ब्रायन कीथ (2001)। राष्ट्र का प्रताड़ित शरीर: हिंसा, प्रतिनिधित्व, और एक सिख "प्रवासी" का गठन। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 84. आईएसबीएन 978-0-8223-2615-1. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त। सिख मातृभूमि का आह्वान पहली बार 1930 के दशक में किया गया था, जो तेजी से विघटित हो रहे साम्राज्य को संबोधित था।
7. ^ शनि, जियोर्जियो (2007)। वैश्विक युग में सिख राष्ट्रवाद और पहचान। रूटलेज। पी। 51. आईएसबीएन 978-1-134-10189-4. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त। हालांकि, खालिस्तान शब्द पहली बार मार्च 1940 में एक स्वतंत्र सिख राज्य को दर्शाने के लिए डॉ. वीएस भट्टी द्वारा गढ़ा गया था। डॉ. भट्टी ने मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के जवाब में 'खालिस्तान' नामक एक पुस्तिका में एक अलग सिख राज्य का मामला बनाया था।
8. ^ बियानचिनी, स्टेफ़ानो; चतुर्वेदी, संजय; इवेकोविच, राडा; समदर, रणबीर (2004)। विभाजन: राज्यों और दिमागों को नया आकार देना। रूटलेज। पी। 121. आईएसबीएन 978-1-134-27654-7. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त। लगभग उसी समय, लगभग चालीस पत्रों का एक पैम्फलेट भी सामने आया, जिसका शीर्षक था 'खालिस्तान' और इसके लेखक थे मेडिकल डॉक्टर वी.एस. भट्टी।
9. ^ एबी गुप्ता, शेखर; सुब्रमण्यम, निरुपमन (15 दिसंबर 1993)। "आप सैन्य आंदोलन के माध्यम से खालिस्तान नहीं पा सकते: जगत सिंह चौहान"। इंडिया टुडे। 4 फरवरी 2021 को मूल से संग्रहीत। 29 नवंबर 2019 को लिया गया।

10. [^]बीबीसी "भारत ने टूटो को कनाडा में संदिग्ध सिख अलगाववादियों की सूची दी"। रॉयटर्स। 22 फरवरी 2018.3 फरवरी 2021 को मूल से संग्रहीत। 22 मई 2018 को लिया गया। 1990 के दशक में सिख विद्रोह खत्म हो गया। उन्होंने राज्य के नेताओं से कहा कि उनका देश खालिस्तान नामक स्वतंत्र सिख मातृभूमि के लिए आंदोलन को फिर से शुरू करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा।
11. [^]अली, हैदर (6 जून 2018)। "ब्लू स्टार की सालगिरह पर खालिस्तान समर्थक सिखों द्वारा स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया"। दैनिक पाकिस्तान। 6 जुलाई 2020 को मूल से संग्रहीत। 25 जून 2018 को लिया गया।
12. [^]"यूके: पाकिस्तानी मूल के विधायक ने कश्मीर, खालिस्तान की आजादी के लिए लंदन में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया"। स्कॉल करें। 27 जनवरी 2018. 3 फरवरी 2021 को मूल से संग्रहीत। 29 जून 2018 को लिया गया।
13. [^]भट्टाचार्य, अनिरुद्ध (5 जून 2017)। "खालिस्तान समर्थक समूह ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह मनाने के लिए कनाडा में कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं"। हिंदुस्तान टाइम्स। 4 फरवरी 2021 को मूल से संग्रहीत। 6 जुलाई 2018 को लिया गया।
14. [^]बीबीसी "सिख उग्रवाद का नया ब्रांड: सुवे, तकनीक-प्रेमी खालिस्तान समर्थक युवा सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी बन गए"। हिंदुस्तान टाइम्स। 4 मार्च 2021 को मूल से संग्रहीत। 27 अप्रैल 2018 को लिया गया।
15. [^]मजूमदार, उशीनोर. "कनाडा, ब्रिटेन और इटली में सिख चरमपंथी आईएसआई के साथ या स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं"। आउटलुक इंडिया। 20 जुलाई 2019 को मूल से संग्रहीत। 8 जून 2018 को लिया गया। क्या यह स्पष्ट है कि कौन सा "विदेशी हाथ" इस पूरे गठजोड़ को चला रहा है? उ. पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य आईएसआई को पंजाब में चरमपंथ के प्रमुख अपराधी के रूप में इंगित करते हैं। (अमरिंदर सिंह भारतीय पंजाब मुख्यमंत्री)
16. [^]"सिमरनजीत सिंह मान ने विवाद खड़ा किया, संगरूर की जीत जरनेल सिंह भिंडरावाले को समर्पित की: खालिस्तान समर्थक नेता के बारे में जाने", फ़र्स्टपोस्ट, 27 जून 2022, 27 जून 2022 को मूल से संग्रहीत, 27 जून 2022 को पुनः प्राप्त
17. [^]"संगरूर उपचुनाव परिणाम लाइव: AAP ने भगवंत मान की सीट खो दी, SAD-A ने 6,800 वोटों से जीत हासिल की", हिंदुस्तान टाइम्स, 26 जून 2022, 26 जून 2022 को मूल से संग्रहीत, 26 जून 2022 को पुनः प्राप्त किया गया
18. [^]वालेस, पॉल (1986)। "भारत में सिख बहुसंख्यक राज्य में सिख एक "अल्पसंख्यक" के रूप में"। एशियाई सर्वेक्षण. 26 (3): 363-377. डीओआई: 10.2307/2644197। आईएसएसएन 0004-4687. जेएसटीओआर 2644197। भारत के 10,378,979 सिखों में से 8,000,000 से अधिक पंजाब में केंद्रित थे
19. [^]जॉली, सिख रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स (1988), पृ. 6.
20. [^]पूरेवाल, नवतेज के. (2017)। हाशिये पर रहना: शहरी दक्षिण एशिया में आश्रय तक सामाजिक पहुंच। रूटलेज। आईएसबीएन 978-1-351-74899-5. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनः प्राप्त। विभिन्न सिख समूहों के बीच झगड़े उन्नीसवीं सदी में हल हो गए जब महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर से सतलुज नदी तक पंजाब को एकीकृत किया।
21. [^]पैटन, केनेथ जे. (2015)। ब्रिटिश साम्राज्य का ऐतिहासिक शब्दकोश। रोवमैन और लिटिलफ्रील्ड। पी। 470. आईएसबीएन 978-0-8108-7524-1. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनः प्राप्त। ठीक दो साल बाद दूसरे संघर्ष के परिणामस्वरूप सिखों को पूरी तरह अधीन कर लिया गया और उनकी शेष भूमि भी इसमें शामिल कर ली गई।
22. [^]फेयर, डायस्पोरा इंवॉल्वमेंट इन इंसर्जेसीज़ (2005), पृ. 127.
23. [^]एक्सल, ब्रायन कीथ (2001)। राष्ट्र का प्रताड़ित शरीर: हिंसा, प्रतिनिधित्व, और एक सिख "प्रवासी" का गठन। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 85. आईएसबीएन 978-0-8223-2615-1. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनः प्राप्त। अकालियों ने लाहौर प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन को सिखों के साथ विश्वासघात और महाराजा रणजीत सिंह के समय से, जो ऐतिहासिक रूप से एक सिख क्षेत्र था, उसे हड़पने के प्रयास के रूप में देखा।
24. [^]टैन, तार्ई योंग; कुदैस्या, ज्ञानेश (2005) [पहली बार 2000 में प्रकाशित], दक्षिण एशिया में विभाजन के बाद, रूटलेज, पी। 100, आईएसबीएन 978-0-415-28908-5 पंजाब (एक मुस्लिम बहुल प्रांत) पर मुस्लिम राज्य थोपने का मुस्लिम लीग का घोषित इरादा सिखों के लिए अभिशाप था... सिखों ने लाहौर प्रस्ताव के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान चलाया... सभी राजनीतिक मतों के सिख नेताओं ने यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान का 'पूरे दिल से विरोध' किया जाएगा।
25. [^]एक्सल, ब्रायन कीथ (2001)। राष्ट्र का प्रताड़ित शरीर: हिंसा, प्रतिनिधित्व, और एक सिख "प्रवासी" का गठन। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 84. आईएसबीएन 978-0-8223-2615-1. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनः प्राप्त। एकजुट भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ, जिसने सभी समूहों से "सांप्रदायिक" मतभेदों को दूर करने का आह्वान किया, 1930 के दशक की शिरोमणि अकाली दल पार्टी ने एक सिख पंथ (समुदाय) के प्रस्ताव के आसपास रैली की जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलग था।
26. [^]शनि, जियोर्जियो (2007)। वैश्विक युग में सिख राष्ट्रवाद और पहचान। रूटलेज। पी। 52. आईएसबीएन 978-1-134-10189-4. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 19 मार्च 2022 को पुनः प्राप्त। खालिस्तान की कल्पना एक धार्मिक राज्य के रूप में की

- गई थी, जो 'मुस्लिम' पाकिस्तान की दर्पण-छवि थी, जिसका नेतृत्व संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली कैबिनेट की सहायता से पटियाला के महाराजा ने किया था।
27. [^] शाह, मेहताब अली (1997), पाकिस्तान की विदेश नीति: कूटनीति पर जातीय प्रभाव 1971-1994, आईबीटॉरिस, आईएसबीएन 978-1-86064-169-5, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत, 5 अक्टूबर 2020 को पुनः प्राप्त किया गया
 28. [^] हिल, के.; सेल्टज़र, डब्ल्यू.; लीनिंग, जे.; मलिक, एसजे; रसेल, एसएस; मेकिंसन, सी. (2003), ए डेमोग्राफिक केस स्टडी ऑफ फोर्सिड माइग्रेशन: द 1947 पार्टिशन ऑफ इंडिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एशिया सेंटर, 6 दिसंबर 2008 को मूल से संग्रहीत
 29. [^] मैकलियोड, डब्ल्यूएच (1989), द सिख्स: हिस्ट्री, रिलिजन एंड सोसाइटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 978-0-231-06815-4
 30. [^] ए बी सी डी ई एफ फेयर, डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट इन इंसर्जेसीज़ (2005), पी। 129.
 31. [^] "पंजाब राज्य के बाहर के गुरुद्वारे"। सिख धर्म का प्रवेश द्वार। 30 नवंबर 1999। 2 मार्च 2021 को मूल से संग्रहीत। 17 अक्टूबर 2020 को लिया गया।
 32. [^] फेयर, डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट इन इंसर्जेसीज़ (2005), पृ. 130.
 33. [^] ए बी सी डी ई फेयर, डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट इन इंसर्जेसीज़ (2005), पी। 128.
 34. [^] ए बी सी फेयर, डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट इन इंसर्जेसीज़ (2005), पी। 134.
 35. [^] ए बी सी डी ई एफ जी एच जेटली, राजश्री। 2006. "भारत में खालिस्तान आंदोलन: राजनीति और राज्य शक्ति की परस्पर क्रिया।" आधुनिक समाजशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा 34(1):61-62। जेएसटीओआर 41421658।
 36. [^] "हिंदू-सिख संबंध - मै"। द ट्रिब्यून। चंडीगढ़, भारत: ट्रिब्यून इंडिया. कॉम। 3 नवंबर 2003. 5 जून 2011 को मूल से संग्रहीत।
 37. [^] चावला, मुहम्मद इकबाल। 2017. 1984 का खालिस्तान आंदोलन: एक आलोचनात्मक प्रशंसा।
 38. [^] "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966" (पीडीएफ)। भारत सरकार। 18 सितंबर 1966. 19 जनवरी 2012 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत।
 39. [^] स्टेनली वोल्वर्ट (2005)। भारत . कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस. पी। 216. आईएसबीएन 9780520246966. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 11 मार्च 2022 को पुनः प्राप्त।
 40. [^] मित्रा, सुब्रत के. (2007), द पज़ल ऑफ़ इंडियाज़ गवर्नेंस: कल्चर, कॉन्टेक्ट एंड कम्पेरेटिव थ्योरी, एडवांसेड इन साउथ एशियन स्टडीज़: रूटलेज, पी। 94, आईएसबीएन 978-1-134-27493-2, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत, 6 मार्च 2018 को पुनः प्राप्त
 41. [^] सिंह, खुशवंत (2004), "द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एंड अदर अकाली डिमांड्स", ए हिस्ट्री ऑफ द सिख्स: वॉल्यूम 2: 1839-2004, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, डीओआई : 10.1093/acprof:oso/9780195673098.001.0001, आईएसबीएन 978-0-19-567309-8
 42. [^] रे, जयंत कुमार (2007), भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पहलू, 1700 से 2000: दक्षिण एशिया और विश्व, पियर्सन एजुकेशन इंडिया, पी। 484, आईएसबीएन 978-81-317-0834-7, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत, 16 अगस्त 2019 को पुनः प्राप्त किया गया
 43. [^] ए बी सी अक्षयकुमार रमनलाल देसाई (1991)। सरकारी अराजकता और संगठित संघर्ष का विस्तार। लोकप्रिय प्रकाशन. पीपी. 64-66. आईएसबीएन 978-81-7154-529-2.
 44. [^] ए बी सी डी फेयर, डायस्पोरा इन्वॉल्वमेंट इन इंसर्जेसीज़ (2005), पी। 135.
 45. [^] ए बी सी डी पंड्या, हरेश (11 अप्रैल 2007)। "भारत में सिख आतंकवादी नेता जगजीत सिंह चौहान का 80 वर्ष की आयु में निधन"। न्यूयॉर्क टाइम्स। 20 दिसंबर 2016 को मूल से संग्रहीत। 17 फरवरी 2017 को लिया गया।
 46. [^] ए बी एक्सल, द नेशनल टॉर्चर्ड बॉडी (2011), पीपी. 101-
 47. [^] थॉमस, जो (14 जून 1984)। "लंदन सिख ने निर्वासित प्रमुख की भूमिका निभाई"। न्यूयॉर्क टाइम्स। 24 अक्टूबर 2018 को मूल से संग्रहीत। 24 अक्टूबर 2018 को लिया गया।
 48. [^] ए बी सी दुलत, एएस(13 दिसंबर 2020)। "पंजाब में उथल-पुथल भरे दौर की उत्पत्ति"। द ट्रिब्यून। चंडीगढ़, भारत। 24 जून 2021 को मूल से संग्रहीत। 13 जून 2021 को लिया गया। भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं उठाई या अकाली आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से आगे नहीं बढ़े, जबकि वह खुद अंत तक बातचीत के लिए तैयार थे।
 49. [^] ए बी स्टीवंस, विलियम के. (19 जून 1984)। "पंजाब छापेमारी: अनुत्तरित प्रश्न"। द न्यूज यॉर्क टाइम्स। 24 जून 2021 को मूल से संग्रहीत। 12 जून 2021 को लिया गया।

50. [^]बी सी डी ई चीमा, जुगदीप एस (2008), द सिख सेपरेटिस्ट इंसर्जेसी इन इंडिया: पॉलिटिकल लीडरशिप एंड एथनोनेशनलिस्ट मूवमेंट्स, भारत: सेज पब्लिकेशंस, पीपी. 71-75, आईएसबीएन 978-81-321-0538-1, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत, 5 अक्टूबर 2020 को पुनः प्राप्त किया गया
51. [^] शर्मा, संजय (5 जून 2011)। "भजन लाल 'सिख विरोधी, पंजाब विरोधी' छवि के साथ रहते थे"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 10 जून 2011 को मूल से संग्रहीत।
52. [^] स्टीफन, अल्फ्रेड; लिंज़, जुआन जे.; यादव, योगेन्द्र (2011), क्राफ्टिंग स्टेट-नेशंस: इंडिया एंड अदर मल्टीनेशनल डेमोक्रेसीज़ (इलस्ट्रेटेड संस्करण), जेएचयू प्रेस, पी। 97, आईएसबीएन 978-0-8018-9723-8, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत, 5 अक्टूबर 2020 को पुनः प्राप्त किया गया
53. [^] घोष, श्रीकांत. 1997. भारतीय लोकतंत्र पटरी से उतर गया - राजनीति और राजनेता। एपीएच प्रकाशन। आईएसबीएन 978-81-7024-866-8. पी। 95.
54. [^] सिसन, मैरी। 2011. "सिख आतंकवाद।" द सेज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ टेररिज्म (दूसरा संस्करण) में पीपी. 544-545 थाउज़ेंड ओक्स, सीए: सेज प्रकाशन। आईएसबीएन 978-1-4129-8016-6. डीओआई: 10.4135/9781412980173.n368।
55. [^]बी शर्मा, मूलचंद, और एके शर्मा, संपा. 2004. "धर्म के आधार पर भेदभाव, 24 अक्टूबर 2020 को वेबैक मशीन संग्रहीत।" पृष्ठ 108-110 लिंग, जाति, धर्म और विकलांगता के आधार पर भेदभाव। नई दिल्ली: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 2 जून 2010 को मूल से संग्रहीत।
56. [^] स्वामी, प्रवीण (16 जनवरी 2014)। "रॉ प्रमुख ने ऑपरेशन ब्लूस्टार की तैयारी में एमआई6 से परामर्श किया"। द हिंदू। चेन्नई, भारत। 18 जनवरी 2014 को मूल से संग्रहीत। 9 अगस्त 2018 को लिया गया।
57. [^] सिंह, खुशवंत. 2004. सिखों का इतिहास, खंड II: 1839-2004। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 337.
58. [^] सुब्रमण्यम, एलएन (12 अक्टूबर 2006)। "ऑपरेशन ब्लूस्टार, 05 जून 1984"। भारत रक्षक मॉनिटर. 3 (2). 30 जून 2020 को मूल से संग्रहीत। 17 मई 2020 को लिया गया।
59. [^]बी "पंजाब समझौते में सिख नेता की हत्या"। लॉस एंजिल्स टाइम्स। टाइम्स वायर सर्विसेज। 21 अगस्त 1985। 29 जनवरी 2016 को मूल से संग्रहीत। 9 अगस्त 2018 को लिया गया।
60. [^] टुली, मार्क; जैकब, सतीश (1985)। अमृतसर: श्रीमती गांधी की अंतिम लड़ाई (5 संस्करण)। जे. केप. पी। 147. आईएसबीएन 978-0-22-402328-3. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 14 जनवरी 2022 को लिया गया।
61. [^] वोल्पर्ट, स्टेनली ए., एड. (2009)। "भारत"। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका।
62. [^]बी गेट्स, स्कॉट; रॉय, कौशिक (4 फरवरी 2014)। "पंजाब में उग्रवाद और प्रति-विद्रोह"। दक्षिण एशिया में अपरंपरागत युद्ध: छाया योद्धा और आतंकवाद विरोधी। एशगेट प्रकाशन। पी। 167. आईएसबीएन 978-1-40-943706-2. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 14 जनवरी 2022 को लिया गया।
63. [^] दीवानजी, अंबरीश के. (4 जून 2004)। "कोई देश कितना ले सकता है इसकी एक सीमा है"। द रेडिफ साक्षात्कार/लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ (सेवानिवृत्त)। Rediff.com। 3 दिसंबर 2019 को मूल से संग्रहीत। 26 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त।
64. [^] वालिया, वरिंदर (20 मार्च 2007)। "सेना ने ब्लूस्टार पर चौकाने वाले तथ्य उजागर किए, लोंगोवाल ने आत्मसमर्पण किया"। द ट्रिब्यून। अमिस्टार. 4 अगस्त 2020 को मूल से संग्रहीत। 14 जनवरी 2022 को लिया गया।
65. [^] जुगदीप एस चीमा (2008)। भारत में सिख अलगाववादी विद्रोह: राजनीतिक नेतृत्व और जातीय-राष्ट्रवादी आंदोलन। सेज पब्लिशिंग इंडिया। पृ. 114-। आईएसबीएन 978-9351509530. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 13 मार्च 2022 को लिया गया।
66. [^] पंजाब आंदोलन पर श्वेत पत्र। नई दिल्ली: भारत सरकार प्रेस. 1984. पी. 40. ओएल 1839009एम. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 14 जनवरी 2022 को लिया गया।
67. [^] करीम, अफ़सीर (1991)। आतंकवाद का मुकाबला, पाकिस्तान फैक्टर। लांसर प्रकाशक। पृ. 33-36. आईएसबीएन 978-8170621270. 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत। 13 मार्च 2022 को लिया गया।
68. [^] "Pakistan would have recognised Khalistan". Rediff.com. 3 June 2004. Archived from the original on 29 January 2009. Retrieved 20 June 2006.
69. [^] Andrew, Christopher M.; Mitrokhin, Vasili (2005). The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World. Allen Lane. p. 336. ISBN 978-0-7139-9359-2. Archived from the original on 30 March 2022. Retrieved 30 September 2022.

70. ^ Andrew, Christopher (2008). *The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World*. DIANE Publishing Company. ISBN 978-1-4223-9312-3. Archived from the original on 30 March 2022. Retrieved 30 September 2022.
71. ^ Subramanian Swamy (1992). *Building a New India: An Agenda for National Renaissance*. UBS Publishers' Distributors. p. 18. ISBN 978-81-85674-21-6. Archived from the original on 30 March 2022. Retrieved 6 September 2022. The 1984 Operation Bluestar became necessary because of the vast disinformation against Sant Bhindranwale by the KGB, and repeated inside Parliament by the Congress Party of India.
72. ^ Guidry, John A., Michael D. Kennedy, and Mayer N. Zald, eds. 2000. *Globalizations and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere*. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-06721-3. p. 319.
73. ^ Nanavati, G. T. 9 February 2005. "Report of the Justice Nanavati Commission of Inquiry (1984 Anti-Sikh Riots) Archived 3 February 2021 at the Wayback Machine" 1. New Delhi: Ministry of Home Affairs. Archived from the original 27 November 2014. Retrieved 18 May 2020. Also available via People's Archive of Rural India Archived 7 May 2020 at the Wayback Machine.
74. ^ a b "What about the big fish?". *Tehelka*. Anant Media. 25 August 2005. Archived from the original on 13 September 2012.
75. ^ Singh, Swadesh Bahadur. 31 May 1996. "Cabinet berth for a Sikh." *Indian Express*.
76. ^ Kumar, Ram Narayan, et al. 2003. *Reduced to Ashes: The Insurgency and Human Rights in Punjab*. South Asia Forum for Human Rights. p. 43. Available via Committee for Information and Initiative on Punjab.
77. ^ *In Depth: Air India* Archived 18 March 2005 at the Wayback Machine – The Victims, CBC News Online, 16 March 2005
78. ^ "Free. Fair. Fearless". *Tehelka*. Archived from the original on 12 September 2012.
79. ^ "Jagmeet Singh now rejects glorification of Air India bombing mastermind". *CBC News*. 15 March 2018. Archived from the original on 2 October 2020. Retrieved 4 August 2020.
80. ^ a b c Gilligan, Andrew (21 April 2008). "Ken's adviser is linked to terror group". *London Evening Standard*. Archived from the original on 12 June 2009. Retrieved 26 May 2009.
81. ^ Bolan, Kim (9 February 2008). "Air India bombmaker sent to holding centre". *Ottawa Citizen*. Archived from the original on 9 November 2012. Retrieved 31 May 2009.
82. ^ "Convicted Air India bomb-builder Inderjit Singh Reyat gets bail". *CBC News*. 9 July 2008. Archived from the original on 10 July 2008. Retrieved 10 June 2009.
83. ^ "Sikh Temple Sit-In Is a Challenge for Punjab." *The New York Times*. 2 February 1986.
84. ^ a b c d e f g Van Dyke, The *Khalistan Movement* (2009), p. 990.
85. ^ Singh, I. (10 July 2012). "Sarbat Khalsa and Gurmata". *SikhNet*. Archived from the original on 12 June 2013. Retrieved 15 March 2013.
86. ^ "Sant Nirankari Mission". *nirankari.org*. Archived from the original on 13 January 2022. Retrieved 13 January 2022.
87. ^ "Gunmen Slaughter 32 on Bus in India in Bloodiest Attack of Sikh Campaign". *The Philadelphia Inquirer*, 7 July 1987. Page A03.
88. ^ a b c d Gargan, Edward (10 October 1991). "Envoy of Romania Abducted in India". *The New York Times*. Archived from the original on 23 October 2018. Retrieved 17 February 2017.
89. ^ Gurharpal Singh, *Ethnic Conflict in India* (2000), Chapters 8 & 9.
90. ^ Gurharpal Singh, *Ethnic Conflict in India* (2000), Chapter 10.
91. ^ "Amnesty International report on Punjab". *Amnesty International*. 20 January 2003. Archived from the original on 3 December 2006.
92. ^ "The Tribune, Chandigarh, India – Punjab". *Tribuneindia.com*. Archived from the original on 5 June 2011. Retrieved 27 September 2015.
93. ^ "SAD (A) to contest the coming SGPC elections on Khalistan issue: Mann". *PunjabNewline.com*. 14 January 2010. Archived from the original on 15 July 2011.
94. ^ "Balwinder Singh Sandu | Gallantry Awards". *gallantryawards.gov.in*. Archived from the original on 31 October 2020. Retrieved 29 October 2020.
95. ^ "Gunmen Wound India Ambassador". *Los Angeles Times*. 21 August 1991. Archived from the original on 10 October 2012. Retrieved 26 December 2011.

96. ^ "World Notes India". Time. 21 October 1991. Archived from the original on 30 September 2007. Retrieved 14 January 2022.
97. ^ "Secret Injustice: The Harpal Singh Case | Part 1: Flashback". The Sikh Sentinel. 17 September 2003. Archived from the original on 8 March 2012.
98. ^ Talbot, India and Pakistan (2000), p. 272.
99. ^ Simmons, Mary Kate (1998). Unrepresented Nations and Peoples Organization: yearbook. Martinus Nijhoff Publishers. p. 187. ISBN 978-90-411-0223-2. Archived from the original on 30 March 2022. Retrieved 3 August 2018.
100. ^ "Issue Paper INDIA: Sikhs in Punjab 1994–95". Immigration and Refugee Board of Canada. February 1996. Retrieved 31 May 2009.
101. ^ "अमेरिकी अदालत ने खालिस्तान कमांडो फोर्स का समर्थन करने के लिए खालिद अवान को दोषी ठहराया"। संयुक्त राज्य अटार्नी कार्यालय। 20 दिसंबर 2006. 15 जनवरी 2012 को मूल से संग्रहीत। 26 दिसंबर 2011 को पुनःप्राप्त.
102. ^ महमूद, सिंधिया. 5 मई 1997. "टेड एल्बर्स को फैक्स"। ओरोनो, मेन: संसाधन सूचना केंद्र.
103. ^ दस्तावेज़ीकरण, सूचना और अनुसंधान शाखा। 17 फरवरी 1997। "भारत: पंजाब पर चार विशेषज्ञों से जानकारी, सूचना अनुरोध का जवाब #IND26376.EXI"। ओटावा: कनाडा का आप्रवासन और शरणार्थी बोर्ड ।
104. ^ "हत्यारों की रक्षा: पंजाब, भारत में दण्ड से मुक्ति की नीति: I. सारांश"। मनुष्य अधिकार देख - भाल। 9 अक्टूबर 2006. 12 अक्टूबर 2008 को मूल से संग्रहीत । 11 जनवरी 2010 को पुनःप्राप्त .
105. ^ विशेष प्रसारण सेवा.: डेटलाइन - जॉर्ज नेगस द्वारा प्रस्तुत, 28 अगस्त 2008 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत
106. ^ "द हिंदू: राय/समाचार विश्लेषण: क्या सत्य की तलाश के बिना न्याय संभव है?" . द हिंदू । 9 सितंबर 2005. 22 मई 2008 को मूल से संग्रहीत।
107. ^ "भारत: पंजाब में दंडमुक्ति समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर"। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए। 25 जून 2009 को मूल से संग्रहीत ।
108. ^ "एएसडब्ल्यू"। मनुष्य अधिकार देख - भाल। 1992. 12 अक्टूबर 2012 को मूल से संग्रहीत । 11 जनवरी 2010 को पुनःप्राप्त .
109. ^ "भारत: पंजाब में अत्याचारों के लिए न्याय देने का समय"। मनुष्य अधिकार देख - भाल। 18 अक्टूबर 2007. 13 जनवरी 2022 को मूल से संग्रहीत । 14 जनवरी 2022 को लिया गया ।
110. ^ "दस्तावेज़ - भारत: पंजाब में दण्ड से मुक्ति और यातना के चक्र को तोड़ें | एमनेस्टी इंटरनेशनल"। अंतराष्ट्रीय क्षमा। 2003. 12 जून 2011 को मूल से संग्रहीत । 11 जनवरी 2010 को पुनःप्राप्त .
111. ^ सहगल, मंजीत (23 सितंबर 2019)। "पंजाब: तरनतारन में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चार आतंकवादी गिरफ्तार"। इंडिया टुडे । 15 दिसंबर 2019 को मूल से संग्रहीत । 27 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
112. ^ सेवा, ट्रिब्यून समाचार। "एनआईए ने तरनतारन विस्फोट मामले में 4 की हिरासत की मांग की"। ट्रिब्यून इंडिया समाचार सेवा । 27 दिसंबर 2019 को मूल से संग्रहीत । 27 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
113. ^ पुंज, बलबैर (16 जून 2005)। "खालिस्तान का भूत"। द सिख टाइम्स । 4 दिसंबर 2018 को मूल से संग्रहीत । 23 जनवरी 2007 को पुनःप्राप्त .
114. ^ "पाक के समर्थन से खालिस्तान समर्थक संगठनों द्वारा पंजाब में आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही है: खुफिया सूत्र"। डीएनए इंडिया । 26 दिसंबर 2019. 27 दिसंबर 2019 को मूल से संग्रहीत । 27 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
115. ^ नंजप्पा, विक्की (26 दिसंबर 2019)। "आईबी द्वारा पंजाब में संभावित आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद हाई अलर्ट घोषित किया गया"। वनइंडिया । 27 दिसंबर 2019 को मूल से संग्रहीत । 27 दिसंबर 2019 को लिया गया ।
116. ^ "सरबत खालसा 2015 से आधिकारिक संकल्प"। सिख24.कॉम । 11 नवंबर 2015. 12 नवंबर 2015 को मूल से संग्रहीत । 12 नवंबर 2015 को लिया गया .
117. ^ "मान के खालसा से मिलने आते ही खालिस्तान के नारे लगे"। इंडियन एक्सप्रेस । 25 जुलाई 2015। 27 अगस्त 2015 को मूल से संग्रहीत । 14 अगस्त 2015 को लिया गया .
118. ^ "खालिस्तान आंदोलन का संभावित पुनरुत्थान: सिख प्रवासी की भूमिका - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा मंच"। stsfors.org । 16 अक्टूबर 2015 को मूल से संग्रहीत । 2 अप्रैल 2022 को पुनःप्राप्त .
119. ^ "सूचना अनुरोधों के जवाब"। irb-cisr.gc.ca . 5 जून 2018. 14 अगस्त 2019 को मूल से संग्रहीत । 14 अगस्त 2019 को लिया गया ।
120. ^ "पंजाब में ब्लूस्टार की सालगिरह पर खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए"। डेक्कन हेराल्ड । 6 जून 2015. 25 जुलाई 2015 को मूल से संग्रहीत । 14 अगस्त 2015 को लिया गया .

121. ^ "पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के समारोह के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगे" । इंडियन एक्सप्रेस । 26 जुलाई 2015. 29 अगस्त 2015 को मूल से संग्रहीत । 14 अगस्त 2015 को लिया गया .
122. ^ कुमार, राम नारायण (1997), सिख अशांति और भारतीय राज्य: राजनीति, व्यक्तित्व और ऐतिहासिक पूर्वव्यापी , अजंता, आईएसबीएन 978-81-202-0453-9वेबैक मशीन पर 15 अगस्त 2018 को रेडिफ़ ऑन द नेट आर्काइव्ड में उद्धृत
123. ^ पेटीग्रेव, द सिक्स ऑफ़ द पंजाब (1995) , पीपी. 188-197।
124. ^ वैन डाइक, द खालिस्तान मूवमेंट (2009) , पी. 992.
125. ^ए बी वैन डाइक, द खालिस्तान मूवमेंट (2009), पी. 991.
126. ^ए बी "पंजाब में एक और खालिस्तान आंदोलन की कोई संभावना नहीं: रक्षा विशेषज्ञ" । हिंदुस्तान टाइम्स। एनआई. 19 मार्च 2016.6 मई 2018 को मूल से संग्रहीत। 5 मई 2018को लिया गया.
127. ^ दिल्ली, सिमरत (दिसंबर 2007)। "सिख प्रवासी और खालिस्तान की खोज: राज्य का दर्जा या आत्म-संरक्षण की खोज?" (पीडीएफ) . शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान। 17 अगस्त 2019 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 26 मई 2009 को पुनःप्राप्त .
128. ^ "' भिंडरावाले 2.0' : कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में सक्रिय । ' पगड़ीधारी, कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले कुछ समय से पंजाब में काफी सक्रिय हैं।
129. ^ सेठी, चितलीन के. (23 फरवरी 2022)। "कट्टरपंथी कार्यकर्ता अमृतपाल ने समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोला, सहयोगी की रिहाई सुनिश्चित की" । दिप्रिंट । 24 फरवरी 2022 को मूल से संग्रहीत । 24 फरवरी 2022 को लिया गया ।
130. ^ "कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह मुद्दा: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उनकी 'रिहाई' की मांग करते हुए HC में दायर की गई" . द फाइनेंशियल एक्सप्रेस । 19 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत । 19 मार्च 2022 को लिया गया ।
131. ^ [128] [129] [130]
132. ^ "दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह को नापसंद करते थे, उनका फोन ब्लॉक कर दिया" । ट्रिब्यून इंडिया ।
133. ^ मथारू, सोनल (25 अक्टूबर 2022)। "प्रखर वक्ता, 'भिंडरावाले 2.0' - कौन हैं अमृतपाल सिंह, दीप सिद्धू की वारिस पंजाब दे के नए 'प्रमुख'" । दिप्रिंट । 4 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
134. ^ "अमृतपाल सिंह का उत्थान और पतन" । ट्रिब्यून इंडिया ।
135. ^ दीप सिद्धू के परिजनों का कहना है, "इस बात से अनजान कि कैसे अमृतपाल सिंह ने खुद को 'वारिस पंजाब दे' का प्रमुख घोषित कर दिया" । फाइनेंशियलएक्सप्रेस । 24 फरवरी 2022 । 4 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
136. ^ "अमृतपाल सिंह: अमृत संचार युवाओं की 'नशा मुक्ति' पर ध्यान केंद्रित करेगा" । ट्रिब्यून इंडिया ।
137. ^ "'खालिस्तान को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए...': तूफ़ान के रूप में अमृतपाल सिंह आज आज़ाद होंगे" । हिंदुस्तान टाइम्स । 24 फरवरी 2022। 4 जुलाई 2022 को लिया गया ।
138. ^ "अमृतपाल सिंह | एक कट्टरपंथी उपदेशक" । द हिंदू । 25 फरवरी 2022। आईएसएसएन 0971-751एक्स । 4 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
139. ^ मुगल, रिया (22 मार्च 2022)। "खालिस्तान: गैरकानूनी सिख अलगाववादी आंदोलन जिससे भारतीय अधिकारी चिंतित हैं" । सीएनएन । 4 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
140. ^ "'वारिस पंजाब दे' प्रमुख अमृतपाल सिंह एनएसए के तहत पंजाब के मोगा से गिरफ्तार; असम की डिब्रूगढ़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया" । द हिंदू । 23 अप्रैल 2022। आईएसएसएन 0971-751एक्स । 4 जुलाई 2022 को लिया गया ।
141. ^ "देखें: सिखों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के विरोध में खालिस्तानी झंडा फहराया" । फ्री प्रेस जर्नल । 20 मार्च 2022. 21 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत । 21 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त .
142. ^ साइमन लिटिल; जूली नोलिन. "पंजाब में तनाव बीसी तक फैलने पर पत्रकार पर कथित तौर पर हमला किया गया" वैश्विक समाचार । 21 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत । 21 मार्च 2022 को पुनःप्राप्त .
143. ^ "भारतीय उच्चायोग: लंदन विरोध के बाद राजनयिक को बुलाया गया" । बीबीसी समाचार। 20 मार्च 2022 । 25 जून 2022 को लिया गया ।
144. ^ "कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले में अमृतपाल सिंह का बहनोई मुख्य आरोपी" । हिंदुस्तान टाइम्स । 24 जून 2022 । 25 जून 2022 को लिया गया ।
145. ^ "खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आग लगाने की कोशिश की" । द ट्रिब्यून इंडिया ।

146. ^ "वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों द्वारा वरिष्ठ भारतीय पत्रकार पर हमला" । डेक्कन हेराल्ड । 26 मार्च 2022 । 25 जून 2022 को लिया गया ।
147. ^ "बीबीसी में पंजाब में तनाव फैलने पर पत्रकार पर कथित तौर पर हमला | Globalnews.ca" । वैश्विक समाचार । 25 जून 2022 को लिया गया ।
148. ^ "मिस्टर तरनजीत सिंह संधू...: खालिस्तान समर्थक ने अमेरिका में भारतीय दूत को दी धमकी | देखें" । हिंदुस्तान टाइम्स । 26 मार्च 2022। 25 जून 2022 को लिया गया ।
149. ^ अनिरुद्ध भट्टाचार्य (27 अप्रैल 2018)। "कनाडाई पुलिस ने खालिस्तानी 'अलगाववादी' हरदीप निज्जर को 24 घंटे की हिरासत के बाद रिहा कर दिया" । हिंदुस्तान टाइम्स.
150. ^ "मार्च के बाद से दूसरा हमला: सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगा दी गई; अमेरिका ने हिंसा की निंदा की" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 4 जुलाई 2022. आईएसएसएन 0971-8257 । 4 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
151. ^एबी "अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ बर्बरता, आगजनी के प्रयास की निंदा करता है"। ट्रिब्यून इंडिया।
152. ^ "अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बर्बरता की निंदा करता है" । रॉयटर्स । 4 जुलाई 2022 । 4 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
153. ^ "टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास में 'गर्म ' प्रदर्शन , एक को गिरफ्तार किया गया । द ग्लोब एंड मेल । 9 जुलाई 2022 । श्री निज्जर की मृत्यु में भूमिका।
154. ^ यूसुफ, नादिन (18 सितंबर 2022)। "कनाडाई सिख की हत्या के पीछे भारत हो सकता है - टूडो" । बीबीसी समाचार । 18 सितंबर 2022 को लिया गया ।
155. ^ टास्कर, जॉन पॉल (18 सितंबर 2022)। "टूडो ने भारत सरकार पर कनाडाई सिख नेता की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया" । कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ।
156. ^ कुमार, देवेश (19 सितंबर 2022)। "नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराएंगे: कनाडा के सिख सांसद ने न्याय दिलाने की कसम खाई" . टकसाल । 19 सितंबर 2022 को लिया गया ।
157. ^एबी शिह, गेरी; मेहरोत्रा, करिश्मा (19 सितंबर 2022)। "कनाडा के सहयोगियों ने भारत के खिलाफ आरोपों में शामिल होने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया"। वाशिंगटन पोस्ट। आईएसएसएन0190-8286. 19 सितंबर 2022को लिया गया।
158. ^ पेटीग्रेव, द सिख्स ऑफ द पंजाब (1995) , पृ. 24.
159. ^ अग्रवाल, जे.सी.; अग्रवाल, एसपी (1992), पंजाब का आधुनिक इतिहास, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पी। 117, आईएसबीएन 978-81-7022-431-0
160. ^एबी पुरी, हरीश के., परमजीत सिंह जज, और जगरूप सिंह सेखों। 1999.पंजाब में आतंकवाद: जमीनी हकीकत को समझना। नई दिल्ली: हर-आनंद प्रकाशन। पीपी. 68-71.
161. ^एबी फेयर, डायस्पोरा इंवॉल्वमेंट इन इंसर्जेसिज़ (2005), पी। 133.
162. ^एबी "काउंसिल सामान्य स्थिति 2005/427/सीएफएसपी 6 जून 2005, आतंकवाद से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों के आवेदन पर सामान्य स्थिति 2001/931/सीएफएसपी को अद्यतन कर रही है और सामान्य स्थिति 2005/220/सीएफएसपी को निरस्त कर रही है" (पीडीएफ)। यूरोपीय संघ। 6 जून 2005. पृ. 5.1 जून 2013 को मूल से संग्रहीत(पीडीएफ)। 31 मई 2009को पुनःप्राप्त.
163. ^ "वर्तमान में सूचीबद्ध संस्थाएँ (आतंकवादी संगठन-एड)" । सार्वजनिक सुरक्षा कनाडा। 26 जून 2009 को मूल से संग्रहीत । 31 मई 2009 को पुनःप्राप्त .
164. ^एबी सी डी ई एफ माइलवस्की, टेरी (28 जून 2007)। "कनाडा में सिख राजनीति। प्रतीक और सूट। सिख उग्रवाद मुख्यधारा की कनाडाई राजनीति में प्रवेश करता है"। सीबीसी. 1 जून 2009 को मूल से संग्रहीत। 26 दिसंबर 2011को पुनःप्राप्त.
165. ^एबी "प्रतिबंधित आतंकवादी समूह"। सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध के लिए यूके कार्यालय। 15 जून 2009 को मूल से संग्रहीत। 24 मई 2009को पुनःप्राप्त.
166. ^ "आतंकवादी बहिष्करण सूची" । यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटरटेररिज्म एंड काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म । 29 दिसंबर 2004। 13 मई 2009 को मूल से संग्रहीत । 14 जनवरी 2022 को लिया गया ।
167. ^ "परिशिष्ट एफ: आर्थिक मोर्चे पर आतंकवाद का मुकाबला" (पीडीएफ) । यू। एस। स्टेट का विभाग। पी। 2. 10 नवंबर 2020 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 31 मई 2009 को पुनःप्राप्त .
168. ^ महमूद (1996) , पृ. 328
169. ^ मार्था क्रेशॉ, एड. (1995), संदर्भ में आतंकवाद , पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, पी। 656, आईएसबीएन 978-0-271-01015-1, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत , 29 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त किया गया

170. ^ एटकिंस, स्टीफन ई. (2004), आधुनिक विश्वव्यापी चरमपंथियों और चरमपंथी समूहों का विश्वकोश (सचित्र संस्करण), ग्रीनवुड पब्लिशिंग ग्रुप, पी। 404, आईएसबीएन 978-0-313-32485-7, 30 मार्च 2022 को मूल से संग्रहीत , 26 जून 2009 को पुनः प्राप्त
171. ^ "विदेशी आतंकवादी संगठन"। अमेरिकी विदेश विभाग। 8 अप्रैल 2008। 13 मई 2009 को मूल से संग्रहीत।
172. ^ "कानून प्रवर्तन मामले: अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण रणनीति रिपोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स और कानून प्रवर्तन मामलों का ब्यूरो"। यू। एस। स्टेट का विभाग। मार्च 2008. 16 अगस्त 2019 को मूल से संग्रहीत। 8 जून 2009 को पुनःप्राप्त .
173. ^ आतंकवाद निरोधक समन्वयक का कार्यालय (अप्रैल 1996)। "1995 वैश्विक आतंकवाद के पैटर्न"। अमेरिकी वैज्ञानिकों का संघ। 22 जनवरी 2009 को मूल से संग्रहीत। 30 मई 2009 को पुनःप्राप्त .
174. ^ प्रताप, अनीता (22 मई 1996)। "भारत में बस विस्फोट में कम से कम 14 लोग मारे गए: यह दो दिनों में दूसरा बम विस्फोट है"। नई दिल्ली: सीएनएन . 8 नवंबर 2012 को मूल से संग्रहीत। 14 जनवरी 2022 को लिया गया।
175. ^ "सीएनएन - विघ्न डालने के लिए बनाया गया घातक बम - 21 अप्रैल 1996"। cnn.com। 8 नवंबर 2012 को मूल से संग्रहीत। 14 जनवरी 2022 को लिया गया।
176. ^ "जालंधर विस्फोटों के पीछे KZF"। इंडियन एक्सप्रेस। 19 जून 2006. 5 जून 2009 को मूल से संग्रहीत। 26 दिसंबर 2011 को पुनःप्राप्त .
177. ^ "वैश्विक आतंकवाद के पैटर्न: 1997 - परिशिष्ट बी"। यू। एस। स्टेट का विभाग। 1997. 23 नवंबर 2010 को मूल से संग्रहीत। 25 मई 2009 को पुनःप्राप्त .
178. ^ नायर, कुलदीप (22 फरवरी 1999)। "यह फिर से कट्टरवाद है"। Rediff.com। 5 जनवरी 2012 को मूल से संग्रहीत। 26 दिसंबर 2011 को पुनःप्राप्त .
179. ^ जुएर्गेन्समेयर, मार्क (14 अक्टूबर 2004)। "भिंडरावाले से बिन लादेन तक: धार्मिक हिंसा को समझना" (पीडीएफ)। खुद। पी। 30. 13 जुलाई 2011 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत। 26 मई 2009 को पुनःप्राप्त .



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com